जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

चूरू, शुक्रवार 28 नवम्बर, 2025

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडू राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 2000 व 2001 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्रप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवई, जस्टिस सूर्यकान्त, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंदुरकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुर में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्‌भुत व प्रशंसनीय है। सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपित सिब्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधयेक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नही कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025 त्रुटिपूर्ण था, जिसमें खण्डपीठ ने राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिये समय सीमा तीन माह तय की थी। इसी फैसले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिन्दुओं पर राय मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधयेक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न 1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नही कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :-

"165.3: The discharge of the Governor's function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion."

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वतः मंजूरी (Deemed Assent) को संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथककरण के सिद्धान्त के विरूद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह् लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के कानून बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सचमुच में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय देना या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होग, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में सही सत्मार्ग है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतान्त्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग-2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेन्ट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतावलम्बियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोका जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वंय के लिए एक बडी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वंय अनुच्छेद 21 में शब्द 'स्पमि' की व्याख्या करते हुये माना है कि स्पमि यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जमानत की अर्जियों तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी ही जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बडे वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेशी तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा नं0 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अतः प्रश्न उठाया जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक

पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत

विकास, विश्वास और सुगमता की नई राह पर राजस्थान

अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रहीं, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।

राजस्थान में सड़क तंत्र को मज़बूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की 'मिसिंग लिंक' सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सरकार के विजन के अनुरूप 8,194 करोड़ की लागत से 6,249 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों का विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि 2,547 करोड़ की लागत से 8 राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालयों से संपर्क को सुगम बनाने के लिए 5,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इसका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं की सहज पहुंच के रूप में दिखाई दे रहा है। डबल इंजन सरकार की नीतियों के अनुरूप राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अब तक 600 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि 457 किलोमीटर सड़कों पर कार्य प्रगति पर है।

रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 10 आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) और 14 आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 33 आरओबी और 14 आरयूबी पर कार्य जारी है। इसके साथ ही, 11 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 15 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। इन संरचनाओं ने न केवल सड़क सुरक्षा को मज़बूती दी है, बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत भी सुनिश्चित की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 तक राजस्थान का कुल सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क घनत्व अब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92.66 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में कनेक्टिविटी और पहुंच में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राज्य में कुल 39,408 गांव अब सड़कों से जुड़े हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्ग को उच्च गति यात्रा के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें सक्रिय हैं।

यह नेटवर्क न केवल राजस्थान के आंतरिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से निर्बाध संपर्क भी सुनिश्चित कर रहा है। राजस्थान की सड़क नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण व्यापक है - यह समठा विकास का माध्यम बन चुकी है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। गांवों से मंडियों तक उत्पादों की सुगम आवाजाही से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उद्योगों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि सड़कें विकास की धमनियां हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। सड़क निर्माण में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस अभियान के परिणामस्वरूप राजस्थान में न केवल सड़क तंत्र मजबूत हुआ है, बल्कि लोगों के जीवन में सहजता, सुरक्षा और सुगमता आई है। सड़कों के इस सुविचारित नेटवर्क ने प्रदेश को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच चुका है।

राजस्थान आज उस दिशा में अग्रसर है जहां सड़कें केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का सड़क तंत्र मज़बूती, सुरक्षा और गुणवत्ता के नए मानक स्थापित कर रहा है। सड़क से विकास की दिशा निकलती है और राजस्थान इस दिशा में देश के अठाणी राज्यों में शामिल हो चुका है। सड़कों पर दौड़ते वाहन अब केवल यातायात का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने की यात्रा का हिस्सा हैं।

अलका सक्सेना,
अतिरिक्त निदेशक सेनि.,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
राजस्थान

सवालों के उत्तर मिलने चाहिए/सवाल कई हैं

रचना सिद्धा

पिछले दिनों दो खबरें प्रमुखता से अखबार में दिखी और कई दिनों तक चली। न केवल प्रिंट मीडिया में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आज इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज में दो बेटियों की जीवनलीला दहेज के दानव ने समाप्त कर दी। पहली खबर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी खबर राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में बेटी को जला कर मार डाला गया और राजस्थान में बेटी ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी तीन साल की बच्ची को भी मार डाला। दोनों ही दुर्घटनाओं की विस्तृत छानबीन चल रही है। परंतु प्रथम दृष्टया दोनों ही मामले दहेज हत्या के बताए जा रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं के बारे में पढ़कर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दुर्घटना की। निक्की जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई। दोनों बहन के साथ साथ जेठानी देवरानी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाइटर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की की सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थी। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ दहेज को लेकर अक्सर मार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह पूरा किया। अब उससे 35 लाख रुपये लाने की बात कही जा रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की जहां सरकारी स्कूल की एक व्याख्याता ने अपनी तीन साल की मासूम और अबोध बच्ची को गोद में बिठाकर अपने को आग के हवाले कर दिया। उस बच्ची को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां उसे गोद में क्यों बिठा रही थी। संजू के पिता ओमाराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा है कि संजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कार के अलावा भी उनकी बहुत सी मांगें पूरी की थीं। लेकिन उनकी और मांगों की सूची खत्म नहीं हो रही थी और इसके लिए संजू को प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि बच्ची के जन्म के बाद स्थितियां और खराब हो गई थीं। पुलिस को भी संजू का आत्महत्या नोट मिला है जिसमें उसने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजू की आत्महत्या के समय घर पर कोई नहीं था।

दोनों ही दुर्घटनाओं से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। निक्की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। वह अपना पार्लर चलाती थी। संजू सरकारी नौकरी कर रही थी। दोनों ही परिपक्व उम्र की थीं। फिर भी वे दहेज के लिए अत्याचार क्यों सह रही थीं? निक्की और संजू के माता पिता क्यों बार बार लड़के वालों की दहेज की मांग को पूरा कर रहे थे? उन्होंने उन्हें अपने पास वापस क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं निक्की और संजू या उनके पीहर वालों ने घरेलू हिंसा और दहेज के मामले में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजू की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले दहेज का मामला दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी दहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजू के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेटियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि लड़के और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें दहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पाती?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को दोयम दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। दहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने चाहिए। क्यों उन्हें अपनी बेटी की मौत के बाद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराना याद आता है?

क्यों दहेज की मांगों को वे सिरे से खारिज नहीं कर देते? क्यों शादी के बाद भी बरसों तक वे बेटी के ससुराल वालों की मांग पूरी करते रहते हैं? क्यों वे अपनी बेटी को इतनी हिम्मत देते हैं कि बेटी अपने घर वापस आकर नये सिरे से अपने जीवन की शुरूआत कर सकें क्यों विदा करते समय वे यह नहीं कहते कि यह घर आज भी तुम्हारा उतना ही अपना है जितना पहले था? कभी भी किसी भी समय उसे अपने इस घर में आने का साहस भर कर क्यों विदा नहीं करते अपनी बेटियों को? क्यों वे नहीं कहते - हम हैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये पांच शब्द बेटियों को बहुत हिम्मत दे जाते हैं। इसके विपरीत हमारे यहां विदा करते समय कहा जाता है अब वही तुम्हारा घर है। उस घर की मान, मर्यादा और इज्जत का खयाल तुम्हें ही रखना है। अब समय आ गया है कि शादी के बाद पीहर से विदा करते समय हम लड़कियों को किसी भी परिस्थिति में पीहर के साथ का वादा करें। उन्हें यह भरोसा दिला कर भेजें कि इस घर पर उसका पहले जितना ही हक है। हम यह अच्छी तरह समझ लें कि दहेज देकर खरीदा गया लड़का किसी भी हालत में अच्छा और सुसंस्कृत लड़का नहीं हो सकता। शादी के समय बेटी को दिए जाने वाले उपहार और दहेज के अंतर को जरूर समझ लें।

- रचना सिद्धा,
लेखक

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी

उदयपुर, (का.सं.)। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में यूरिया खाद को लेकर भारी भीड़ रही। वहां सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया। खाद को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हुई। मावली उपखंड के थामला गांव में थामला ग्राम सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीलरों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला समिति पर खाद की आपूर्ति पहुंचते ही किसानों की भीड़ लग गई। वहां सुबह 10 बजे तक करीब 300 से अधिक किसान लंबी कतारों में खड़े होकर खाद लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह से कतार में लगे किसानों का नंबर नहीं आने पर उनमें आक्रोश था।

अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए और किसानों के आक्रोश के बीच मौके पर मावली पुलिस भी आई। बाद में पुलिस और समिति कर्मचारियों ने मिलकर किसानों को शांति से खाद वितरण कराने की अपील की लेकिन किसानों ने कहा कि वे सुबह से आए और 11 बजे गए लेकिन उनको खाद नहीं मिली।

राशिफल 28 नवम्बर 2025

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2082, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 2.50 तक, व्याघात योग गिन 11.05 तक, विष्टिकरण दिन 12.23 तक चन्द्रमा कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।

रवियोग रात्रि 2.50 से आरम्भ होगा। भद्रा दिन 12.23 तक रहेगी। आज शनि मार्गी प्रात 9.25 पर होगा। आज दुर्गाष्टमी, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चट - सूर्योदय से 8.19 तक, लाभ अमृत 8.19 से 10.56 तक, शुभ 12.15 से 1.33 तक, चट 4.10 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल - 10.30 से 12.00 तक, सूर्योदय 7.00 सूर्यास्त 5.29

मेष

आर्थिक -वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सम्भव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

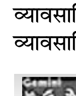

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कर्क

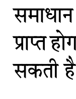

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

सिंह

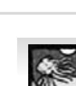

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। आज परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

कन्या - विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

तुला

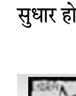

तुला - व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

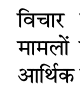

घर परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

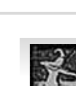

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों-रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

मकर - आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी।

कुंभ

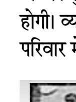

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य में सफलता से मनोबल आत्मविश्वास बडेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन

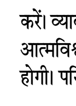

घर-परिवार के कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 211 प्रभात चूरू, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

सुप्रीम कोर्ट "आधार कार्डधारियों" को सीधे ही नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं लगता?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर उसके सम्मुख चल रही बहस के दौरान संकेत दिया, आधार कार्ड अपने आप नागरिक होने का अधिकार नहीं देता

- **"आधार कार्ड" का सीमित मकसद था, कुछ सरकारी सुविधाएं, जैसे राशन उपलब्ध कराना। अगर किसी पड़ोसी देश से कोई भारत आता है, मजदूरी करने, तो उसे राशन की सुविधा, मानवीय कारणों से दी जाती है, पर, क्या उसे यह सुविधा देने का अर्थ उसे नागरिकता देना भी हो जाता है।**
- **कपिल सिब्बल ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय का फोकस, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि प्रक्रिया की शुद्धता। सिब्बल ने आगे कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, पर, आधार कार्ड से संभावना मेरे पक्ष में है कि मैं नागरिक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर इस कारण मुझे नागरिकता मिल सकती है, अगर गलत मिली है तो सरकार यह साबित करे, न्यायिक प्रक्रिया से, तथा तभी मेरी नागरिकता रद्द की जा सकती है।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवंबर। आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे घुसपैठियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक गैर-नागरिक को आधार कार्ड होने पर मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक कल्याण लाभ सभी तक पहुंचे, और यह दस्तावेज़ स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा करने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार कार्ड "नागरिकता का पूर्ण प्रमाण" नहीं है। बैंच ने कहा, "इसलिए हमने कहा था कि यह दस्तावेजों की सूची में एक दस्तावेज़ होगा। यदि किसी का नाम हटाया जाता है, तो उसे हटाने का नोटिस दिया जाएगा।"

आधार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आधार एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन पाने के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और श्रमिक के रूप में काम करता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को उस दस्तावेज़ की प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार है, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग "पोस्ट ऑफिस" नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने शाहरुख, देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमायरा से जवाब मांगा

- **आरोप है कि चारों ने विमल गुटखे में "केसर बादाम" बताकर भ्रामक प्रचार किया।**

जयपुर, 27 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने, "विमल गुटखे के दाने-दाने में केसर का दम" बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित, विमल गुटखा ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्लाई करती है और तीनों अभिनेता व अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवाद में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपए में आता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्पीकर का पद भी छीना भाजपा ने नीतीश से

शपथ ग्रहण के बाद भाजपा ने नीतीश को लगातार दूसरा झटका दिया

- **एक दिसंबर को जद (यू) विधायक नरेन्द्र नारायण यादव प्रोटैम स्पीकर के रूप में विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसी समय नए स्पीकर के नाम की घोषणा करेंगे। अगर कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुआ तो वे निर्विरोध स्पीकर घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा ने इस पद के लिए वरिष्ठ दलित नेता प्रेम कुमार का नाम आगे किया है।**
- **आंतरिक सूत्रों ने बताया कि नीतीश पर केन्द्र का भारी दबाव है, फिलहाल वे "वेट एण्ड वॉच" की नीति पर चल रहे हैं।**
- **इस बार स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश हों, पर सरकार पर नियंत्रण भाजपा का ही होगा।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवंबर। बिहार के सत्ता गलियारों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर अपना दबदबा मजबूत कर लिया है। जेडीयू से अति महत्वपूर्ण गृह विभाग छीनने के बाद, भाजपा ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्पीकर पद छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया है, जो कि शपथ ग्रहण के बाद उनके लिये दूसरा बड़ा झटका है।

नव-निर्वाचित बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, जब सभी 243 विधायकों को जेडीयू के प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव शपथ दिलायेंगे। प्रारंभिक औपचारिकताओं के 2 दिसंबर तक समाप्त होने के साथ ही, नये स्पीकर का चुनाव होगा, जो भाजपा के पक्ष में एकतरफा प्रतीत हो रहा है।

भाजपा ने पहले ही गया के 9 बार के विधायक और वरिष्ठ दलित नेता प्रेम कुमार का नाम इस प्रतिष्ठित पद के लिए प्रस्तावित कर दिया है। उनके नाम की औपचारिक घोषणा सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जा सकती है।

यदि चुनाव होता है, तो अगले दिन मतदान कराया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जेडीयू अब इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, केन्द्र के जबरदस्त दबाव के कारण नीतीश कुमार ने भाजपा से आगे टकराव से बचने के लिए "प्रतीक्षा करो और देखो" की रणनीति अपनाई है। गृह विभाग छिन जाने और अब स्पीकर पद भी जाता हुआ दिखाई देने की स्थिति में, गठबंधन में जेडीयू की सौदेबाजी की ताकत बहुत कम हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सत्ता का संतुलन निर्णायक रूप से बदल चुका है। नीतीश मुख्यमंत्री भले ही बने रहें, लेकिन अब प्रशासनिक फैसले भाजपा नेतृत्व द्वारा, खासकर दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही, लिए जाएंगे।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास तैयार है प्लान बी

अगर नेतृत्व ने उन्हें बदलने या डीके शिवकुमार को लाने के संकेत दिए तो.......

- **सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने अगर नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए तो सिद्धारमैया विकल्प के रूप में अपने करीबी का नाम आगे कर सकते हैं, जैसे जी. परमेश्वरा, जो एक प्रभावशाली दलित नेता हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ मे बता रहे हैं।**
- **बताया जाता है कि यह रणनीति पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, जो सिद्धारमैया समर्थक हैं, के घर पर बनाई गई है।**
- **हालांकि, डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए खुलकर कोई जिज्ञासा जाहिर नहीं की, पर, वे पुराने वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, जिसमें यह वादा भी शामिल है कि सिद्धारमैया ढाई साल बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और डीकेएस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस के भीतर 'लीडरशिप गेम्स' का कर्नाटक संस्करण गुरुवार को तेज हो गया।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा अब पूरी तरह सतर्क है और जरूरत पड़ते ही दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने की तैयारी में है कि शीर्ष पद पर वही बने रहें। इस सप्ताह उन्होंने पार्टी में पैदा हुई 'उलझन' को स्वीकार किया था और कहा था कि पार्टी को अब इस पर 'पूर्ण विराम' लगा देना चाहिए। इसके बाद सूत्रों का कहना है कि वे 'वेट-एंड-वॉच' मोड में हैं।

सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से जरा भी संकेत मिला कि उनके प्रतिद्वंद्वी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार , जो सार्वजनिक रुप से मुख्यमंत्री पद के प्रति झुकाव को नकार चुके हैं, को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो सिद्धारमैया के समर्थक तुरंत सक्रिय हो जाएंगे।

सूत्रों ने कहा, और यदि पार्टी नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर फिर भी अड़ती है, तो सिद्धारमैया खेमे की योजना है कि नामों की एक वैकल्पिक सूची पार्टी के समक्ष सामने रखी जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में बहुविवाह पर रोक लगी

- **असम विधानसभा ने गुरुवार यह बिल पास किया।**

गुवाहटी, 27 नवंबर। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।

बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।

इस "असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी" बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट में जापान पर निर्भरता कम करना चाहता है रेल्वे

जापान लीकी केबल सिस्टम और शिकान्सेन रैक्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, जबकि रेल्वे उसके सस्ते विकल्प तलाश रहा है

- **जापान इस प्रोजैक्ट का 80 प्रतिशत खर्च उठा रहा है। सवाल यह है कि रेल्वे की सस्ते विकल्प ढूंढने की रणनीति जापान को कहीं नाराज़ ना कर दे।**
- **रेल्वे अगस्त 2027 में सूरत से वापी के बीच 256 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर हाई स्पीड ट्रेन की विश्वसनीयता, रख रखाव, टिकाऊपन और उपलब्धता का परीक्षण करेगा। रेल मंत्री ने 2029 तक बुलेट ट्रेन शुरु होने की संभावना जताई।**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2027 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना के तहत सूरत से वापी खंड में 100 किलोमीटर की दूरी पर 250 किमी/घंटा की गति से विश्वसनीयता, उपलब्धता, रखरखाव और स्थिरता का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था, "508 किलोमीटर लंबे गलियारे की पूरी लंबाई 2029 में शुरू हो जाएगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।"

भारत के पहले हाई-स्पीड रेल गलियारे के लिए लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक कार्यों की प्रगति हो रही है। हालांकि, जापान और भारत के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और रोलिंग स्टॉक पर मतभेदों के कारण समय और लागत में वृद्धि हो रही है। जापान, जो इस परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण कर रहा है, लीकी कोऑक्सिकल सिस्टम (एलसीएक्स) सिस्टम की तैनाती और शिंकान्सेन रैक की पसंद पर जोर दे रहा है।

भारत यूरोपीय निर्माताओं से रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता को आधी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, जो जापान द्वारा 49 दस-कोच हाई-स्पीड ट्रेन सैट्स के लिए उद्धृत की गई कीमत से लगभग आधी है। अधिकारियों ने बताया, जापान ने इस आपूर्ति को ई-10 शिंकान्सेन रैक के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि पश्चिमी देशों से यह स्टॉक लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदा जा सकता है।

लागत को कम करने और जापान पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्टैंडर्ड गेज ट्रेनसेट्स के स्वदेशी निर्माण की योजना को तेज कर दिया है, जो वर्तमान में सरकारी -स्वामित्व वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले सप्ताह सूरत एचएसआर स्टेशन की समीक्षा यात्रा के बाद, बीईएमएल को इन ट्रेनसेट्स को 2027 की शुरुआत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है दो प्रोटोटाइप रैक सूरत-वापी खंड में विश्वसनीयता उपलब्धता रखरखाव व स्थिरता परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाएंगे।

भारतीय रेलवे ने लीकी केबल सिस्टम के बजाय 'ओपन सोर्स'

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों पर छापे मारे

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण पर रिश्वत देने के मामले में यह कार्यवाही हुई।**

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डो-अमेरिकन व्यापारिक समझौता अभी जल्दी ही फाइनल होने वाला नहीं है?

हालांकि, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उनकी टीम, बार-बार ढिंढोरा पीट रही है कि "ट्रेड डील" की केवल घोषणा ही होनी बची है

- **कृषि उत्पाद व डेयरी प्रोडक्ट्स पर मतभेद अभी भी उसी स्थिति में है, जो बातचीत के प्रथम दिवस से था।**
- **अमेरिका चाहता है, डेयरी, खाद्यान्न के बेचने के लिए उसे खुली छूट मिले। पर, डेयरी प्रोडक्ट्स उन मवेशियों के दूध से तैयार किये जाते हैं, जो पशु बाय प्रोडक्ट्स मिश्रित चारे पर पले होते हैं। अतः भारत की आम जनता सांस्कृतिक (कल्चर) कारणों से इन डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं करेगी। पर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स काफी सस्ते होंगे और इजाज़त मिली तो भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तथा भारत में छोटे-छोटे सहकारी प्रयासों से चल रहा डेयरी उद्योग चौपट हो जाएगा।**

-सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं वाणिज्य मंत्री द्वारा यह उम्मीद जताने के बावजूद, कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग तय होने वाला है, बातचीत में दोनों पक्षों को कोई असली कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सच्चाई यह है कि कई गहरे मतभेद दोनों देशों के बीच बड़ी बाधा बने हुए हैं। दोनों पक्ष शुरुआती समझौते को अंतिम रूप देने की इच्छा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर मतभेद कायम हैं, उन्हें देखते हुए कोई भी समझौता सीमित दायरे वाला ही होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील मांगों पर कितना समझौता करने को तैयार हैं।

सबसे बड़ी रुकावट कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, खासकर अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कुछ अनाज और डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर। अमेरिका चाहता है कि इन पर शुल्क कम हो और डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, सेब, मेवे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (प्रोसैस्ड फूड्स) और एथेनॉल जैसे उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। वहीं भारत के लिए कृषि, विशेषकर डेयरी, खाद्यान्न और जीएम फसलें, एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत का तर्क है कि सस्ते और सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और खान-पान की आदतों की वजह से डेयरी आयात का मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील है, और क्योंकि भारतीय डेयरी कोऑपरेटिव और छोटे डेयरी किसान घरेलू रैगुलेटरी और टैरिफ रुकावटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत ने हमेशा व्यापार समझौतों में डेयरी क्षेत्र को उदारीकरण से बाहर रखा है और इस बार भी यही रुख कायम है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों, खासकर जानवरों के बाय-प्रोडक्ट या जी.एम. कंटैंट वाले चारे पर पलने वाले मवेशियों से बने प्रॉडक्ट्स के लिये अपने बाज़ार खोलना, लोगों के साथ-साथ, रैगुलेटरी चिंताओं को भी बढ़ाता है।

कृषि और डेयरी के अलावा भी, कई क्षेत्र विवाद का कारण बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), पेट्रोकेमिकल और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क कम करे। इसके बदले भारत उम्मीद करता है कि अमेरिका इस्पात, एल्युमिनियम, ऑटो-पुर्ज़े, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क में राहत दे।

रुकावटों में रैगुलेटरी और नॉन टैरिफ रुकावटें भी खास तौर पर शामिल हैं। भारत अपनी रैगुलेटरी ऑटोनोमी बनाए रखना चाहता है, जिसमें, खेती और खाने के इंपोर्ट के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैण्डर्ड तथा जी.एम. प्रॉडक्ट पर रोक शामिल है। लेकिन अमेरिका अपने एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा सरल ट्रेड और कम रैगुलेटरी रुकावटों के लिए जोर दे सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट का मुख्य आरोपी बिलाल वानी एनआईए रिमांड पर

- **एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किये।**

श्रीनगर, 27 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को दिल्ली कार बम विस्फोट के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को सात दिन की रिमांड पर ले लिया। दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने वानी को सात दिन की हिरासत में भेजने का फैसला किया।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के रहने वाले वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन में टेक्निकल बदलाव किए और रॉकेट बनाने की भी कोशिएश की,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

480 दिन के लम्बे इन्तजार के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा

पुराने कार्यकर्ताओं के स्थान पर नए लोगों को मिली जगह

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश भाजपा ने लम्बे इन्जार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बनने के 480 दिन बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस कार्यकारिणी में कुल 34 नाम शामिल हैं।

- **कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव बनाए गए हैं।**
- **इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि मुख्य टीम में विधायक और सांसदों को शामिल नहीं किया है।**

कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव की घोषणा की गई है। इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है जबकि मुख्य टीम में विधायक व सांसदो को शामिल नही किया है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि विधायक और सांसदों को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाएगी, जबकि प्रदेश की कार्यकारिणी में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। हालांकि पिछली कार्यकारिणी में सांसद और विधायकों को प्रदेश टीम में शामिल किया गया था। प्रदेश भाजपा की इस नई टीम में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को शामिल किया है।

इस कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तीनो केंद्रीय मन्त्रियों सहित कुछ संघ से जुड़े लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया है।

मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए है। पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जिनमे पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, बिहारीलाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू माईडा, अल्का मुन्दड़ा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। वही नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, डॉ. ज्योति मिर्धा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह मौजूदा कार्यकारिणी मे भी उपाध्यक्ष थे।

इसके साथ ही विधायक (तिजारा) बाबा बालकनाथ, सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है।

मदन राठौड़ ने अपनी टीम में महामंत्रियों की संख्या भी कम की है। मौजूदा कार्यकारिणी में 5 महामंत्री काम कर रहे थे। नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री बनाए गए हैं।

इनमें भी पिछली कार्यकारिणी के महामंत्रियों में से केवल एक को रिपीट किया गया है। ये श्रवण सिंह बगड़ी हैं। चार को बाहर कर दिया गया है।

इनके अलावा कैलाश मेघवाल, भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री बनाया गया है। विधायक जितेन्द्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा को बाहर किया गया है।नई टीम में मौजूदा टीम में काम कर रहे नेताओं में कुछ को प्रमोट भी किया गया है।

मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है।

एससी मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट करके प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा, ओबीसी मोर्चा की टीम से सीताराम पोसवाल को प्रदेश मंत्री बनाकर प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया है।

भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाक़ात

जयपुर। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने गुरूवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमओ में मुलाक़ात की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इन पदाधिकारियों में प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, मिथलेश गौतम एवं प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, अपूर्वा सिंह ,एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, प्रवक्ता स्टेफ़ी चौहान एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से पार्टी को बूथ स्तर पर मज़बूती लेने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार की शानदार योजनाओं को लाभार्थियों और आमजन तक पहुंचाएं और इसकी कार्ययोजना बनाए। करीब 45मिनट की मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से नियुक्त हुए पदाधिकारियों को आम कार्यकर्ता एवं आम जनता के बीच में रहने की सलाह भी दी।

लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज कुमार सैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 1 सितंबर, 2023 को कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की भर्ती निकाली थी। जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई की शैक्षिणक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ या होने वाला अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे साक्षात्कार के समय संपूर्ण पात्रता अर्जित करने का साक्ष्य देना होगा। याचिका में कहा गया कि आवेदन करते समय याचिकाकर्ता अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला था और साक्षात्कार से पूर्व उसने तय संपर्ण पात्रता हासिल कर ली है। इसके बावजूद भी उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ऐसे में उसे पात्र मानते हुए साक्षात्कार में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

भिवाड़ी में 32 और हनुमानगढ़ में 160 फ्लैट्स बनाएगा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड

आवासन मंडल के सभी रिकॉर्ड तत्काल डिजिटलाइज़ करें : देबाशीष पृष्टि

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड दिसंबर माह में अरावली विहार, भिवाड़ी में 32 और डीटीओ, हनुमानगढ़ में 160 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाएगा। इसके साथ ही जयपुर के सेक्टर-22 प्रताप नगर में भी सामुदायिक केंद्र बनाया जायेगा।

- **जयपुर के प्रताप नगर-सेक्टर 22 में भी सामुदायिक केन्द्र बनाने का निर्णय हुआ**

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने गुरूवार को परियोजना समिति की 175वीं बैठक ली।

इसकी जानकारी नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने दी है। उन्होंने गुरूवार को जयपुर स्थित आवासन मंडल मुख्यालय में परियोजना समिति की 175वीं बैठक ली, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए।

मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने अफसरों को निर्देश दिए कि, राजस्थान आवासन मंडल के सभी अभिलेखों को चरणबद्ध तरीके से पूर्णत: डिजिटाइज करें। उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड से लेकर वर्तमान योजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित किया जाए, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़े, अभिलेखों की खोज और सत्यापन में सरलता आए तथा सभी विभागीय गतिविधियों की गति में भी तेजी आए। डिजिटाइजेशन से भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और मंडल की कार्यशैली और अधिक सुचारु एवं तकनीक-आधारित बनेगी।

बैठक में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में उच्च आय वर्ग (जी प्लस8) के 32 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाने का निर्णय लिया गया। इस स्कीम से अलवर, भिवाड़ी, तिजारा एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार मण्डल की डीटीओ हनुमानगढ़ योजना में मध्यम आय वर्ग- के 160 फ्लैट्स के लिए भी मण्डल अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं समीपस्थ क्षेत्रों के मध्यम आय वर्ग के लोगों को आधुनिक फ्लैट उपलब्ध हो सकेगा। यह दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण दिसंबर माह में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर-22 प्रताप नगर, जयपुर में प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी अनुमोदित किया गया, जिससे योजना के आवंटियों सहित आमजन को एक महत्वपूर्ण सामुदायिक सुविधा उपलब्ध होगी। यह केंद्र प्रताप नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी आय वर्ग के निवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसका निर्माण कार्य जनवरी माह में शुरू किया जाएगा। परियोजना समिति की सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू बंसल ने मानचित्रों के माध्यम से सभी योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और संबंधित जानकारियां साझा की। बैठक में मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव, टी.एस. मीणा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बर्खास्तगी के खिलाफ विभागीय अपील 14 साल लंबित रखना दुखद

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश की विभागीय अपील को 14 साल में भी तय नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने जेवीवीएनएल को कहा है कि वह एक माह में अपील का निस्तारण करे। वहीं अदालत ने जेवीवीएनएल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में हर्जाना राशि याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश महेश कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक विधवा अपने पति की बर्खास्तगी के खिलाफ साल 2011 में पेश विभागीय अपील के निपटारे की प्रतीक्षा कर रही है।

24 तीर्थंकरों ने मानव जाति को दिखाया सही मार्ग : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परम पूज्य सुंदर सागर महाराज ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हुए समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और करूणा का अद्भुत समन्वय है। हमारी सरकार सभी धर्मों के विकास और संरक्षण के लिए समर्पित है। उन्होंने आमजन से आव्हान किया कि वे जैन मुनियों के उपदेशों को न केवल सुने, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। शर्मा गुरूवार को सांगानेर कैम्प कार्यालय में आयोजित आचार्य सुंदर सागर महाराज की दिव्य देशना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस धर्म के 24 तीर्थंकरों ने समय-समय पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता 'अहिंसा परमो धर्म' है। ये एक वाक्य नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। आज पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही है और जैन धर्म का यह संदेश वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी संतो की पद वंदना करते हुए उनका हाथ थामे एसएफएस मानसरोवर स्थित आदिनाथ मंदिर से सांगानेर कैम्प कार्यालय के कार्यक्रम में लेकर आए। इस दौरान मार्ग में पुष्प वर्षा एवं बैंड वादन कर उनका स्वागत-अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में शर्मा को 'मातृ भू सेवक' की मानद उपाधि से अलंकृत भी किया गया।

कॉमर्स कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया

जयपुर (कासं)। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉमर्स कॉलेज में गुरूवार को नवनिर्मित भवन "ब्लॉक बी" का लोकार्पण राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किया। समारोह की शुरूआत अतिथि सत्कार, राष्ट्रगान एवं विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुई।

राज्यपाल ने कहा कि, शिक्षा में स्थापत्य कला का महत्व होता है। इस दृष्टि से वाणिज्य महाविद्यालय (कॉमर्स कॉलेज) के नवनिर्मित भवन का अत्यन्त महत्व है। वाणिज्य, व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें बैंकिग, वित्त, विज्ञापन, प्रबन्धन आदि आते हैं। वाणिज्य से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तथा ध्यान से काम करने की आदत बनती है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला तथा कहा कि 1835-36 में अंग्रजों द्वारा दी गयी शिक्षा नीति में बदलाव कर अब शिक्षा में भारतीयता पर जोर दिया जा रहा है।

विनोवा भावे का नामोल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के साथ ही भारतीय शिक्षा नीति अपनानी चाहिए थी इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गयी शिक्षा नीति की आलोचना भी की। उन्होंने उद्बोधन में प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्रों नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने विश्वविद्यालय को इनसे भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। प्राचीन ज्ञान परम्परा पर बल देते हुए उन्होंने मनोज कुमार, अभिनीत फिल्म पूरब-पश्चिम के गाने "जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनियां को तब गिनती आयी" के माध्यम से कहा कि हमने अपनी संस्कृति और शिक्षा पद्धति से पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है।

पाक निवासी नकली नोट तस्कर को कारावास

जयपुर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्रा लाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले पाक निवासी अभियुक्त रान सिंह को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर इस अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश ने बताया कि लैंड कस्टम स्टेशन, मुनाबाव, बाड़मेर के अधिकारियों से गोपनीय सूचना पर 16 मार्च, 2019 को थार लिंक एक्सप्रेस से भारत आते अभियुक्त को पकड़ा था। टीम को उसके कब्जे से 94 हजार रुपए के भारतीय नकली नोट मिले। वहीं टीम ने उससे एक मोबाइल व 2600 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद की। इस पर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि अभियुक्त 2015 में पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुआ था। इसके बाद वह अपने परिवार सहित टर्म वीजा पर आकर मोरबी में रहने लगा। इस दौरान ही अभियुक्त ने भारत थार लिंक एक्सप्रेस का उपयोग षड्यंत्र रचते हुए पाकिस्तान से भारत देश में नकली नोट लाने के लिए किया। पाकिस्तान में अभियुक्त दूसरे आरोपी कूपजी से मिला और उसने अभियुक्त को भारतीय नकली मुद्रा दी। जांच के बाद एनआईए ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले में आरोपी कूपजी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हैं।

कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाडी टीम ने पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली-बहरोड के पुलिस कांस्टेबल प्रवीण बागोरिया को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी भिवाडी टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके भाई का पुत्र व पुत्री नांगल चौधरी से घर आ रहे थे। तब उनके आगे चल रही अन्य गाड़ी को ओवरटेक करते समय उसके खरोंच आ गई।

तीन साल वाले बीपीएड कोर्स को करने वाले पीटीआई भर्ती के लिए पात्र

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 से जुडे मामले में उन अभ्यर्थियों को भी पात्र माना है, जिन्होंने तीन साल वाला बीपीएड कोर्स कर रखा है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थियों को दो माह में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विमला देवी व 6 अन्य अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।अपील में अधिवक्ता आरडी मीणा और अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2018 में पीटीआई तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आए थे, लेकिन उन्हें एक साल के बजाए तीन साल का बीपीएड योग्यता रखने के आधार पर चयन से बाहर कर दिया था। इस पर एकलपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिसे एकलपीठ ने 2013 में खंडपीठ की ओर से दिए एक आदेश का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि साल 2014 में एनसीटीई ने एक परिपत्र जारी कर पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए तीन साल के बीपीएड पाठ्यक्रम करने वालों को भी पात्र माना है। इस परिपत्र में राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर संशोधन नहीं किया है और यह वर्तमान में भी प्रभावी है। अपील में कहा गया कि एनसीटीई शैक्षिणक पाठ्यक्रम तय करने की विशेषज्ञ और सर्वोच्च संस्था है। इसके अलावा एकलपीठ में सुनवाई के समय एनसीटीई ने अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए पात्र माना था। ऐसे में उन्हें पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 में नियुक्ति दी जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में तीन साल वाले बीपीएड योग्यता वालों को पीटीआई ग्रेड 3 के लिए पात्र नहीं माना गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर अपीलार्थियों को समस्त परिलाभ सहित दो माह में नियुक्ति देने को कहा है।

उर्वरकों की कालाबाजारी व अवैध भंडारण करने वालों के लाइसेंस रद्द करें : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रबी सीजन - 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए तथा विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश से अन्य राज्यों में उर्वरक के परिगमन को रोकने के लिये सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाए। साथ ही, प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण के लिए समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। बैठक में बताया गया कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 1 अप्रेल 2025 से अब तक 11634 औचक निरीक्षण किए हैं। इसके अन्तर्गत कालाबाजारी के मामलों में 589 कारण बताओ नोटिस, 77 अनुज्ञापत्र निलंबन/निरस्तीकरण तथा 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

"सहकार गैलेरी" में दिखेगी सहकारी आंदोलन यात्रा की आकर्षक झलक

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने गुरुवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान (राइसेम) परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत स्थापित की गई सहकार गैलेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने गैलेरी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की। सहकारिता विभाग द्वारा एनसीसीएफ के सहयोग से स्थापित की गई सहकार गैलेरी में सहकारी आन्दोलन की यात्रा को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है।

- **सहकारी आन्दोलन की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को आकर्षक रूप में किया गया प्रदर्शित**

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकार गैलेरी का उद्घाटन करने के बाद इसका अवलोकन किया।

दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता की गौरवशाली यात्रा को दर्शाती यह गैलेरी आगन्तुकों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी। यहां प्रदर्शित सामग्री न केवल सहकारिता के इतिहास, उपलब्धियों और नवाचारों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे छोटे-छोटे सामूहिक प्रयासों से बड़े सामाजिक परिवर्तन संभव हैं। सहकार गैलेरी में सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को क्लिप बोर्ड्स, एक्रेलिक शीट्स, विनायल प्रिन्ट, फोटो फ्रेम्स एवं डिजिटल स्क्रीन्स के माध्यम से आकर्षक रूप में राजस्थानी संस्कृति की थीम पर प्रदर्शित किया गया है। गैलेरी के एक भाग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का परिचय एवं सिद्धान्त, सहकारिता के सिद्धान्त एवं उद्देश्य तथा विशिष्ट व्यक्तियों के उद्धरणों को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अन्य एक भाग में सहकारिता के उद्भव एवं विकास से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् सहकारी विधि का विकास की जानकारी शामिल है।

5.44 करोड़ की बकाया लीज प्रकरण में नीमराना डवलपर्स को जेडीए ट्रिब्यूनल से नहीं मिला स्थगन

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) ट्रिब्यूनल ने मैसर्स नीमराना डवलपर्स को 5.44 करोड़ रु. की बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाने के मामले में अंतरिम स्टे देने से इनकार कर दिया है।

- **जयपुर विकास प्राधिकरण ने गत 14 नवंबर को बिल्डर को नोटिस थमाकर कुर्की की चेतावनी दी थी**

इस प्रकरण में बिल्डर की ओर से अधिवक्ता एस.एस.सोलंकी ने दलील दी थी कि, उनके मुवक्किल ने एयरपोर्ट प्लाजा में भूखंड संख्या 1 की 8236.47 वर्गमीटर जमीन जेडीए से नीलामी में खरीदी थी। इस जमीन पर बनाए गए 207 फ्लैट्स में से उसने 165 फ्लैट्स लोगों को बेच दिए हैं, 25 फ्लैट्स पर इंटीरियर का काम चल रहा है। ऐसे में उससे सिर्फ उन्हीं फ्लैट्स की लीज राशि वसूली जानी चाहिए, जो उसके पास बचे हुए है। परंतु गत 14 नवंबर 2025 को जेडीए ने डवलपर को नोटिस देकर 5.44 करोड़ रुपए की बकाया लीज राशि जमा करवाने का नोटिस दिया और संपत्ति कुर्क की चेतावनी दी। जबकि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग ने 19 फरवरी 2020 को आदेश जारी किया था कि, भवन निर्माता द्वारा फ्लैट्स को अलग-अलग लोगों को बेचने के बाद क्रेता द्वारा ही लीज राशि चुकायी जायेगी। बिल्डर ने वर्ष 2016 में भूखंड आवंटन से लेकर वर्ष 2021 तक की बकाया लीज राशि जेडीए को जमा करवा दी थी, परंतु जेडीए प्रशासन अब यह संपूर्ण राशि डवलपर से लेना चाहता है।

बिल्डर की इस दलील का विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि, यह पूरी कार्रवाई भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 64-ए के तहत की जा रही है। ऐसी स्थिति में जेडीए ट्रिब्यूनल के पास हस्तगत मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वहीं बिल्डर ने यह भी नहीं बताया है कि उसने 165 फ्लैट्स कब-कब और किस तारीख पर लोगों को बेचे है। ऐसे में क्रेताओं पर लीज राशि की गणना किस प्रकार हो सकेगी।

पूरे प्रकरण को सुनने के बाद जेडीए ट्रिब्यूनल ने इस मामले में बिल्डर को अंतरिम स्टे देने से इनकार कर दिया।

ज्वैलर्स की दुकान में हुई 38 लाख की लूट का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी से कुछ ज्वैलरी भी बरामद की, दो बदमाशों की तलाश जारी

अलवर, (निसं)। अलवर में ज्वैलर की दुकान में घुसकर 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने लाया गया तो तीन पुलिसवालों ने कार से उतारा। अस्पताल के अंदर मेडिकल कराने ले जाया गया।

अलवर एसपी ने बताया कि एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी सागर उर्फ संजय यादव निवासी इस्माईलपुर पुलिस थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा का निवासी है। उससे कुछ ज्वैलरी भी बरामद की है। तीनों बदमाश हरियाणा के झज्जर के आसपास के हैं। लूट की वारदात कर वापस वहीं निकल गए थे। अभी पुलिस को दो बदमाशों की तलाश है।

■ **हथियार दिखाकर तीन बदमाश ज्वैलरी की दुकान से 38 लाख के जेवरात लूट कर फरार हो गये थे, पांच दिन से पुलिस तलाश कर रही थी**

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे अलवर शहर के तिजारा रोड पर मोहनलाल सोनी की दुकान राधा ज्वैलर्स में घुसकर हथियारों के दम पर 38 लाख रुपए के जेवर लूट ले गए थे। एक बाइक पर तीन बदमाश आए थे। एक ने हेलमेट लगा रहा था। दो ने मुंह को ढका हुआ था। पहले एक बदमाश दुकान में गया। इसने जाते ही मोहनलाल के गले पर दंराती लगा दी थी। दूसरा बदमाश तिजोरी की तरफ गया। तिजोरी से जेवर अपने बैग में भरने लगा। तीसरा बदमाश बाहर कट्टा लेकर खड़ा रहा। बीच में कुछ सेकेंड तीसरा बदमाश भी दुकान के अंदर गया। उसने सोनी के साथ मारपीट भी की। करीब 1 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर बाइक से चिकानी रोड की तरफ भाग गए थे। अब 5 दिन बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। व्यापारी से मारपीट कर दुकान की तिजोरी से करीब 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले एक बदमाश को 5 दिन में पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी दो फरार हैं। इस मामले को लेकर 5 दिन से व्यापारी वर्ग में रोष था। दो दिन पहले जल्दी बदमाशों के अरेस्ट नहीं होने पर अलवर बंद का आव्हान किया था। एक दिन दो घंटे सर्राफा बाजार बंद रखा गया था।

करंट लगने से किसान की मौत : डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के बासिया मालीफला में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। बोरवेल की मोटर के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी अपने पिता को देखने पहुंची तो वे मृत हालत में मिले।

धम्बोला थाना हेड कॉनि. सोहनलाल ने बताया कि जयंती उतर घना ताबियाड की करंट लगने से मौत हो गई है। जयंती बुधवार देर शाम को खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। खेतों में बोरवेल के पास ही स्टार्टर भी लगा हुआ था। करंट लगने से जयंती ताबियाड बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। देर तक पिता वापस घर नहीं आए तो बेटी रविना पिता को देखने खेतों की तरफ गई। बोरवेल के पास ही पिता बेहोश हालत में पड़े हुए मिले। रविना ने चिल्लाकर लोगो को बुलाया, लेकिन जयंती की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर धंबोला थाने से हेड कॉनि. सोहनलाल, रोशन और विनोद की टीम पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सीमलवाडा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया।

तीन साल से फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पारस जैन के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हेमन्त कुमार के सुपरविजन में स्थाई वारंटीयों की गिरफ्तारी व आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये एरिया डोमीनेशन की कार्रवाई के लिये विषेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठीत पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर हलेड तिराहा पर बिना नम्बरी स्कॉर्पियो कार जिसके श्‍िशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई सहित लम्बे समय से फरार कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर और स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ पिता महावीर प्रसाद धाकड़ निवासी हनुमान कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। हनुमान धाकड़ के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार को कब्जे में रखने, धोखाधड़ी और मारपीट के 11 प्रकरण दर्ज हैं।

■ **आरोपी से बिना नम्बरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में 11 प्रकरण दर्ज हैं**

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर

क्रमांक :- प.46/अअ/उदय/वि.बो/बिड/2025-26/राजकाज नं. 19022496 दिनांक :- 25/11/2025

निविदा सूचना संख्या -06/2025-26 (NIB No. AGM2526A0206)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड उदयपुर एवं डूंगरपुर में जनजाति विकास कार्य, उदयपुर, राजसमन्द एवं डूंगरपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी एवं उद्यान विभाग के कार्यो की ऑनलाईन निविदाऐं ई–प्रोक्युरमेन्ट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से उपयुक्त कार्य हेतु दिनांक 22.12.2025 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsamb.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in (NIB No AGM 2526A0206 & UBN No. 878 to 881 & 883 to 891) पर भी देखा जा सकता है।

राज.संवाद/सी/25/14693 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-।। बीकानेर

क्रमांक-1124 दिनांक-20/11/2025

ई-बोली सूचना संख्या-11/2025-2026

Bid for Permanent Restoration Work on Various Roads SDGH & CD Work NH-62 to Kisturia at Ch 0/500 are invited from interested bidders from 24-11-2025 to 08-12-2025 6.00 PM. and to be opened 09-12-2025 02:00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and PWD Department website. The approximate value of the procurement is Rs 192.75 Lacs.

(महेन्द्र पाल सिंह चालिया)
अधिशाषी अभियन्ता,
सानिवि जिला खंड-।।, बीकानेर

DIPR/C/17382/2025

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

ई-निविदा सूचना दिनांक :- 26/11/2025

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
e-Tender no. RSMM/ CO/GGM (Cont) Cont-12/2025-26 dated 25.11.2025 UBN No. MML2526WSOB00109	झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट माईन्स स्थित बैस केम्प चौराहे से वेलकम गेट तक बाऊंड्रीवाल निर्माण का कार्य। (निविदानुसार) अनुमानित लागतः रू. 26.70 लाख, धरोहर राशिः रू. 53,400/–, निविदा प्रपत्र मूल्य 1180/–

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/25/14690 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

International Year of Cooperatives 2025

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक- प.1/आ.मि / लैब आईटम क्रय/ 2025-26/106 दिनांकः 20.11.2025

ई- बोली विज्ञिप्त वर्ष 2025-26

चिकित्सालय व राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के लिए लैब आईटम आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित मूल निर्माताओं / डिस्ट्रीब्यूटर्स / अधिकृत विक्रेताओं से कुल अनुमानित राशि 14424000/- रू. की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका UBN NO.- AYU2526GLOB00318 है। लैब आईटम क्रय हेतु निविदा फॉर्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक 20.11.2025 सायं 6:00 बजे से एवं स्वीकार करने की अंतिम दिनांक 10.12.2025 सायं 6:00 बजे तक रखी गई है। बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in, https://dipr.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट https://ayurved.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

DIPR/C/17345/2025 निदेशक

डोडा-पोस्त समेत एक गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने डीपीएस सर्किल के पास नाकाबंदी में सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रेलर को रूकवाया। गाड़ी की तलाशी में कुछ नहीं मिला मगर चालक के पास से दो किलो अवैध डोडा–पोस्त मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने यह डोडा–पोस्त खुद के उपयोग के लिए लाना बताया। थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि नाकाबंदी में एक सीमेंट से लदे ट्रेलर को रूकवाया गया। चालक के पास से दो किलो डोडा–पोस्त मिला। इस पर सहीराम विश्रोई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया।

किशोरी से दुष्कर्म

बीकानेर, (निसं)। 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है, जिसे कोटगेट थाना पुलिस तलाश रही है। पीड़िता की मां की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने पुत्र और नाबालिग पुत्री के साथ रहती है। आरोपी अशोक वेटर ठेकेदार है और पुत्र उसके साथ काम करता है। करीब 25 दिन पहले अशोक उसकी पुत्री को बहला–फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और प्रभारी जमानती वारंट से तलब

अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया

जोधपुर, (कासं)। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मयंक बथवाल और प्रभारी अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी को पचास पचास रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग के समक्ष तलब किया है।

आयोग अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा, न्यायिक सदस्य अरुण कुमार अग्रवाल और सदस्य लियाकत अली ने हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। अनीता भरत कुमार गर्ग ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से इजराय प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि 6 सितंबर 2023 को आयोग ने प्रार्थी के पति की मृत्यु पर एक करोड़ रुपए दावा राशि मय ब्याज दो लाख रुपए हरजाना और 50 हजार रूपए वाद व्यय अदा करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 16 अप्रैल 2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थी की रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गत 14 जनवरी को 50 फीसदी राशि का भुगतान 31 मार्च तक प्रार्थी को अदा करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी की ओर से राशि जमा नहीं करने पर 12 अगस्त को खंडपीठ ने बीमा कंपनी को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने का निर्देश दिया और इसके अभाव में प्रार्थी को विपक्षी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की छूट प्रदान की। 9 सितम्बर को विपक्षी के यह कहने पर कि उन्होंने गलत जगह का ड्राफ्ट बना दिया था, खंडपीठ ने विपक्षी को सही डिमांड ड्राफ्ट दो सप्ताह में 15 हजार की कॉस्ट के साथ जमा कराने का आदेश दिया।

■ **हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया**

अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं कर 19 नवंबर को आधी अधूरी राशि 72 लाख 27 हजार 630 रुपए राज्य उपभोक्ता आयोग के नाम से ड्राफ्ट बना कर जमा करवा दी, जबकि विपक्षी को सही राशि का ड्राफ्ट प्रार्थी के नाम से जमा करना था, सो अवमाननाकर्ता को जरिए वारंट तलब किया जाएं।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की पूर्ण पालना नहीं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य आयोग, जोधपुर के समक्ष राशि जमा करने का आदेश दिया था और कहा था कि राशि प्रार्थी को अदा की जाएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी को यह जानकारी होते हुए कि राज्य आयोग का कोई बैंक खाता नहीं है, उन्होंने प्रार्थी के नाम से ड्राफ्ट नहीं बनाकर आयोग के नाम से बनाकर गलत किया है। अवमाननाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है सो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत उनको दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है सो अवमाननाकर्ता को 50 –50 हजार रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया जाता है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभि. विभाग, वृत बारां

भीम BhIM

क्रमांक :- अअ/वृत/बारां/2025-26/1901 दिनांकः 17/11/2025

निविदा सूचना संख्याः 04 से 07/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/कार्य के ठेकेदार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक, दूरसंचार, रेल्वे, सेना अभियांत्रिकी सेवा, अन्य राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/ संगठनों के पास सूचीबद्ध ठेकेदार, जो कि राजस्थान सरकार के "एए" श्रेणी के समतुल्य है भी कार्यो के लिये निविदा हेतु नियमानुसार विहित अठिम धनराशि देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, से निर्धारित प्रपत्रो में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।
निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 19.11.2025 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाईन निविदाएँ इसी वेबसाईट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 19.11.2025 से 04.12.2025 सांय 18:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। वेबसाईट पर दिनांक 05.12.2025 को इस कार्यालय में दोपहर 15:00 बजे निविदा खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्यदिवस को उसी समय पर निविदा खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से चालान की प्रति इस कार्यालय में 05.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पजिकृत स्थाई संवेदक/फर्म पंजीयन जीवित नही होने, संवेदक/फर्म का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
उक्त निविदा एसपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते है :-
1. http://www.eproc.rajasthan.gov.in 2. http://sppp.rajasthan.gov.in

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा/ प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2%	½%	Tender Fees	RISL Fees	
04/ 2025-26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN No.: PHE2526 WSRC08646	150.00	3,00,000/-	75000/-	5000/-	2000/-	12 माह
05/ 2025-26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc, complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Baran. UBN No.: PHE2526WSRC08651	150.00	3,00,000/-	75000/-	5000/-	2000/-	12 माह
06/ 2025-26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Chhabra, Dist. Baran UBN No. PHE 2526WSRC08652	100.00	2,00,000/-	50,000/	2000/-	1500/-	12 माह
07/ 2025-26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Baran, Dist. Baran UBN No.: PHE 2025-26WSRC08653	100.00	2,00,000/-	50,000/	2000/-	1500/-	12 माह

जल ही जीवन है

(आलोक कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियंता
जनस्वा.अभि. विभाग, वृत्त बारां

DIPR/C/17307/2025

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
कार्यालय मुख्य अभियंता (थर्मल डिजाईन), 602, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना : TN-47 (RVU2526GLOB01681)

रा.वि.उ.नि. के केटीपीएस, कोटा हेतु बीबीडी–4760 प्रकार के बीएचईएल लाइनर्स और एसटीपीएस, सूरतगढ़ एवं सीटीपीपी, छबड़ा के लिए कोयला पल्वराइजर्स/मिलों बीबीडी–4772 प्रकार के बीएचईएल लाइनर्स की आपूर्ति हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in (ई–निविदा हेतु), www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/25/14697 RVUN/PR-4305 अधीक्षण अभियन्ता (टी.डी.-I)

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर पालिका, सादड़ी (जिला–पाली) राज. (आपकी सेवा में सदैव तत्पर)
पताः मैन बस स्टेण्ड, सादड़ी
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com

क्रमांक : न.पा.सा./2025/3785–3787 दिनांक 20.11.2025

-:: Notice Inviting Bid ::-

Bid for subject matters of procurement are invited from intreseted bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in) of the state departmental website.

UBN NO :- DLB2526WSOB24772

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी

राज.संवाद/सी/25/14660

RajCOMP Info Services Limited (RISL)
C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL द्वारा निम्न ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं :–

NIB No./ Date/ Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost	Start of sale / Last date
4898/26.11.2025 RIS2526GSRC00057	RFP Regarding rate contract for supply & installation of SSL Certificates for various websites / applications.	9.00 Lacs 18,00,000	02.12.2025 / 10.12.2025

विस्तृत जानकारी हेतु इन वेबसाईट पर सम्पर्क करें – http://risl.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://doitc.rajasthan.gov.in.

Raj.Samwad/C/25/14705 General Manager

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी / निलामी (ERCC/RCC 17)/2025/ई-13391

ई-नीलामी विज्ञप्ति संख्या (ERCC/RCC 17)/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञिप्त से अप्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों / क्वारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क /अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 44 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPR/C/17396/2025 (महावीर प्रसाद मीणा) निदेशक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर

क्रमांकःअअ / सांचोर /2024-25/3011 दिनांकः 20.11.2025

निविदा सूचना संख्याः 12/2025-26
NIB No.: PWD2526A4414

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न सड़को के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रू. 261.60 लाख है

निविदा आवेदन	25 नवम्बर 2025, 9:30 बजे से 15 दिसम्बर 2025, सांय 6:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in http://sppp.rajasthan.gov.in http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http:// eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http:// eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवार यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।
UBN No.
1.UBN PWD2526WS01317413
2.UBN PWD2526WS01317416

(प्रदीप पंवार)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड सांचौर

DIPR/C/17381/2025

अवैध रूप से पेड़ काटने व कोयला कारोबार करने पर प्रशासन सख्त

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में राजकीय भूमि और जंगलों पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने तीन अलग–अलग प्रकरणों में 10 कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 (सीसीए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इनमें से चार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर ने बनेड़ा क्षेत्र में बिना नीलामी हजारों पेड़ काटे व सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर को गायब करने संबंधी मामला सामने आने पर विभागीय जांच करवाई। जांच में दोषी पाए जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक देवकरण टॉक व पटवारी (हल्का बामणिया) भगवत लाल जाट को निलंबित किया गया। साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है एवं तहसीलदार बनेड़ा संतोष कुमार सुनारीवाल के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर को आसींद क्षेत्र के नारायणपुरा गांव के 200 बीघा जंगल में अवैध रूप से पेड़ कटवाने व अवैध तरीके से कोयला माफिया से मिलीभगत कर कोयला बनाकर बाहर भेजने संबंधी प्रकरण सामने आया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच करवाई गई। जिला कलेक्टर ने भू अभिलेख निरीक्षक नरेशनाथ योगी व पटवारी दूल्हेपुरा गारंती बाई मीणा को निलंबित किया, साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है। तहसीलदार आसींद जयसिंह के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

■ **जिला कलेक्टर ने 10 अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध 16 सीसीए की कार्रवाई की, चार को निलंबित किया**

वहीं जिला कलेक्टर को जहाजपुर क्षेत्र में 300 बीघा बिलानाम भूमि पर बबूल के पेड़ काटने व अवैध कोयला कारोबार से संबंधित मामला सामने आया, जिसमें विभागीय जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाये जाने पर तहसीलदार जहाजपुर रवि कुमार मीणा, नायब तहसीलदार खजूरी बद्रीलाल मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक अशोक कुमार धाकड़ व पटवारी हल्का किशनगढ़ अंकित कुमार गुप्ता के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजकीय संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संरक्षण व राजस्व भूमि सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मामूली कहासुनी में किशोर से मारपीट

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में एक कैफ़े में हुई मामूली कहासुनी ने हैवानियत का रूप ले लिया और कुछ युवकों ने एक किशोर को रामसाबास रोड़ स्थित नमक झील क्षेत्र में ले जाकर बेरहमी से पीटा। पिटाई में आरोपियों ने इतनी दरिंदगी की और पीड़ित किशोर को लाठियों और बेल्ट से इस कदर पीटा कि उसकी पीठ, पैर और कूल्हे पर चोट के गहरे लाल निशान बन गए। मारपीट के बाद आरोपी युवक, किशोर को नमक झील में पटककर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित किशोर के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

■ **मारपीट के बाद नमक झील क्षेत्र में किशोर को पटक कर भाग गये आरोपी युवक**

विवादों में रही कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने गुरुवार को इस्तीफा स्वीकार किया। लंबे समय से विवादों में रही प्रो. सुनीता मिश्रा विवादों के बाद से ही छुट्टियों पर थीं। उनके खिलाफ छात्रों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। मिश्रा के बयान को लेकर प्रदेशभर में विरोध हुआ था। कई मंत्रियों ने भी इस पर विरोध जताया था। राजभवन से जारी पत्र में लिखा गया कि कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों पर संभागीय आयुक्त (उदयपुर) की कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

जाकनारी के अनुसार कुलगुरु सुनीता मिश्रा करीब 2 महीने पहले उस समय विवादों में आई थीं जब विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक और अकबर को महान बताया। इस बयान के बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दो माह के लगातार दबाव के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया जिसे राजभवन ने स्वीकार कर उन्हें पदमुक्त कर दिया। उदयपुर में मिश्रा को सुखाडयि यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने उन्हीं के चैंबर में कैद कर दिया था। वे छह घंटे चैंबर में फंसी रहीं थी।विवाद के बाद सामने आई सुनीता मिश्रा ने कहा था कि उनके बयान को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया है।

युवती से दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर, (कासं)। पाक विस्थापित युवती से उसके एक परिचित ने दुष्कर्म किया। उसके फोटो–वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि पाक विस्थापित युवती वर्ष 2014 में यहां आई। उसके साथ ही आरोपी भी 2014 में आया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को उसने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। अब उसे फोटो–वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN
राजस्थान सरकार का उपक्रम
RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

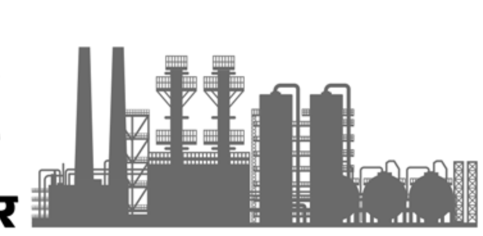

सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

अन्तिम 4 दिन शेष

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

61 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 322 कुल भूखण्ड | 312 औद्योगिक भूखण्ड | 10 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी अंतिम तिथि: 01 दिसम्बर, 2025 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन बिड प्रारम्भ तिथि: 02 दिसम्बर, 2025 (प्रात: 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 04 दिसम्बर, 2025 (सायं 05:00 बजे)

33	आबू रोड़	09	चूरू	34	नागौर	09	उदयपुर
21	अजमेर	10	बीकानेर	07	पाली	03	जयपुर (दक्षिण)
02	अलवर	14	श्रीगंगानगर	26	झालावाड़	01	जयपुर (उत्तर)
07	भिवाड़ी-I	22	किशनगढ़	01	जालोर	28	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
14	भिवाड़ी-II	16	भीलवाड़ा	14	राजसमंद	01	जोधपुर
08	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	05	सवाईमाधोपुर
09	घिलोठ	04	भरतपुर	03	नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राज.संवाद/सी/25/14701

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएपः +91 9001306515, ई-मेलः riico@riico.co.in
आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें
https://riico. rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in

सार-समाचार

गुप्ता के चौथी बार प्रदेश कोषाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की

चूरू (निसं)। प्रदेश कार्यकारिणी ने चूरू के पंकज गुप्ता को पुनः प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाये जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पंकज गुप्ता एक कुशल कार्यकर्ता है और जिले में तीन बार पार्टी की कमान संभाल चुके है। उनका पुनः कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनयन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए उन्होंने जिले के सभी कार्यकर्ताओ की ओर से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड व विधायक हरलाल सहारण सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद् सदस्य ओम सारस्वत ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश ने चूरू का मान बढाया है और पंकज गुप्ता जैसे एक कार्यकर्ता को कोषाध्यक्ष जैसा बडा पद देकर कार्यकर्ताओ को सम्मान दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता फतेहचन्द सोती, जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र काछवाल, भास्कर शर्मा, जिला मंत्री दीनदयाल सैनी, मण्डल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, धर्मेन्द्र राकसिया, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, दौलत तंवर, सरपंच राकेश शर्मा, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, राजीव शर्मा, नीरज जांगिड़, भंवर गुर्जर, ओम इन्दोरिया, कमल बुढ़ाढ़रा, लक्ष्मीनारायण सैन, नितिन बजाज, सोहन सहारण, राकेश ओझा, नोरंग शिलू, गोगराज सैनी, विकास बांठिया, मुंशी चायल, सीपी खत्री, गजानंद गौड़, रामस्वरूप कटारिया, जे.पी. प्रजापत, हरिराम चौपड़ा, सुनील भाऊवाला, पवन बगडिया, विनोद लुणिया, मुरली उंटवालिया, आशीष गोयल, योगेश गौड, रवि दाधीच, विनोद प्रजापत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के गहने और नगदी उड़ाए

बीदासर (निसं)। कस्बे में पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा हुआ ही नही कि बुधवार की रात्रि में कस्बे के वार्ड न 28 दरीबा स्थित व्यापारी मस्जिद के पास एक घर में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के गहने व नगदी चुराकर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबैदा पत्नी गुलाम रसुल जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 28 दडिबा मस्जिद के पास बीदासर ने लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा घर वार्ड न.28 दडिबा व्यापारी बकरा मण्डी के पीछे है मैं तथा मेरे दो लडके व एक लड़की घर में रहते हैं कल रात 12 बजे तक संभाल कर गये थे मैं अपने बच्चों के साथ अपने वृद्ध बीमार सास ससुर के पास सो गये सुबह 6.30 बजे मैने व मेरी बेटी ने आकर देखा तो लोहे वाले गेट का ताला टूटा हुआ दिखा, लोहे का गेट व अन्दर का मोडा खुला पडा था घर के भीतर कमरे मे बनाये स्टोर में रखी लोहे की आलमारी को तोडकर उसमे रखे सोने का हार वजन तैंतीस ग्राम, सोने की पोथ सात ग्राम, नाक की बाली सोने की कान की पति सोने की चार ग्राम, दो ग्राम सोने की कान की पतिया, चांदी की दो जोडी पायजेब सहित अन्य आभुषण लोहे की अलमारी में रखे छोटे बड़े आभुषण व अन्य सामान और नगदी अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। चोर मोहल्ले का ही हो सकता है ऐसा मुझे अंदेशा है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

वाचन एवं विविध कार्यक्रम आयोजित

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान वर्ष 2025 के नवम्बर माह के निर्देशानुसार बुधवार को मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया तथा संविधान दिवस के महत्व एवं शासन में संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता पर व्याख्यान दिया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के नवीन अभियान न्याय आपके द्वार के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी स्कूल ऑफ लॉ के विद्यार्थियों के बीच क्विज, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विधि विद्यार्थियों द्वारा मॉक संसदीय सत्र आयोजित किया गया, जिसमें बाल अधिकारों से संबंधित विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में कुल 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डाबला में रक्तदान शिविर आयोजित

पाटन (निसं)। क्षेत्र के डाबला गांव में गुरुवार को टानिया ह्यूमन हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनहित ब्लड बैंक जयपुर की टीम ने शिविर में कुल 107 यूनिट रक्त एकत्र किया।यह शिविर अजीत सिंह डाबला की पुत्री टानिया की स्मृति में उनकी प्रत्येक पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह पांचवां रक्तदान शिविर रहा, जिसकी शुरुआत टानिया को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई।शिविर में क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समिति द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति पाटन प्रधान सुवालाल सैनी, डॉक्टर रणजीत जाखड, कारगिल योद्धा वीर चक्र जयराम सिंह डाबला, राजपाल डोई, महेंद्र खटाना, सिरोही सरपंच जेपी कसवा, सुनील खटाना, युवा नेता महेश भेडी, बनवारी लाल यादव, सुंदर पापड़ा, वीरेंद्र खटाना बागवाला, राजकुमार जाखड़, प्रवीण जाखड़, श्रवण प्रधान नयाबास, पुष्पेंद्र सैनी और निर्मल यादव सहित क्षेत्र के अनेक लोग उपस्थित रहे।

भामाशाह समाजसेवी सुंदरमल सैनी सम्मानित

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी (निसं)। शेखावाटी अंचल के जाने-माने समाजसेवी, भामाशाह व उधोगपति नीमकाथाना निवासी सुंदर मल सैनी इंडिया प्राइड अवार्ड 2025 से सम्मानित हुए है । सैनी को यह अवार्ड दिल्ली में आयोजित गरिमामय समारोह में उधोग, व्यापार, सेवा व परोपकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान व उत्कृष्ट कार्य के लिए दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया प्राइड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया ।समूह की ओर से देश प्रदेश के अलग-अलग समूहों व ग्रुपों के कारोबारी, उद्यमी, बिल्डर, रियल एस्टेट व समाजसेवा से जुड़ी शख्सियतों का इंडिया प्राइड अवार्ड 2025 के लिए चयनित होने वाली शख्सियतों को मंगलवार को दिल्ली में सम्मानित किया गया। उधोगपति सुंदर मल सैनी के सम्मानित होने पर महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास लक्ष्मनगढ के पदाधिकारी सदस्यों सहित उनके समर्थकों, शुभचिंतकों, सहयोगियों व पारिवारिक सदस्यों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई दी है।

ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन

रतनगढ़ (निसं)। चूरू ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल जोशी ने बताया कि 28 नवंबर को इंडिया पब्लिक स्कूल रतनगढ़ में चूरू जिले कि सीनियर टीम का चयन किया जाएगा। चयन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी राज्यस्तरीय सीनियर तायक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राजस्थान ताइक्वांडों के तत्वावधान में अलवर ताइक्वांडो एसोसिएट्स द्वारा परशुराम इंदौर हॉल में 31 नवम्बर व 1 दिसंबर को ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तायक्वोंडो खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र, राजकीय अस्पताल से जारी आयु सत्यापन प्रमाण पत्र, मूल निवास स्वयं सत्यापित प्रति लेकर आना होगा खिलाडियों के पास ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लैक बेल्ट का सर्टिफ़िकेट होना भी अनिवार्य है।

अंबेडकर भवन में संविधान दिवस मनाया

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी (निसं)। स्थानीय अंबेडकर भवन में संविधान दिवस मनाया गया। अध्यक्षता अंबेडकर विचार मंच समिति के जिला अध्यक्ष अर्जुनलाल वर्मा ने की। यह जानकारी देते हुए मंच के तहसील अध्यक्ष भागीरथमल फदनपुरा ने बताया कि सर्वप्रथम बाबा साहेब अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखें तथा संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। पूर्व जिला अध्यक्ष व अंबेडकरवादी हरफूल सिंह ने संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलवाई। मंच के बीरबल सिंह ने आगुंतुकों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया।

'खेल को खेल की भावना से खेलें, हार-जीत कोई मायने नहीं रखती'

राजलदेसर (निसं)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन पूरे देश भर में चलाया जा रहा है इसी के तहत राजलदेसर नगर मंडल की ओर से पुलिस थाना परिसर में सांसद खेल महोत्सव के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजलदेसर पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार बारूपाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विष्णु प्रजापत, भाजपा जिला प्रवक्ता पवन बोथरा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सांवरमल सुथार, एबीवीपी के नगर मंत्री अभिषेक सैनी, कुलदीप मारू के द्वारा कार्यक्रम का फिता काटकर शुभारंभ

■ सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया

राजलदेसर नगर मंडल की ओर से पुलिस थाना परिसर में सांसद खेल महोत्सव के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई।

किया गया जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस थाना के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार बारूपाल ने कहा आज के युग में बढ़ते हुए नशे के माहौल को देखते हुए युवाओं में खेल के प्रति भावना कम होती जा रही है।

इसीलिए विशेष कर युवाओं को नशे की लत को छोड़ेकर अपने पारंपरिक खेल खेलना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष विष्णु प्रजापत ने कहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि गांव एवं शहर के अंदर ऐसी प्रतिभागी है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता इसी भावना के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिससे खिलाडियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा।

साथ ही खिलाडियों से आग्रह किया कि खेल को खेल की भावना से खेल हार जीत कोई मायने नहीं रखता इस अवसर पर भाजपा जिला प्रवक्ता पवन बोथरा ने कहा इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीम भाग ले रही है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का ध्यान रखती है जिसमें सांसद खेल महोत्सव जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस से खिलाड़ी खेलों के प्रति इंटरेस्ट लेंगे साथ ही नशे की लत से भी दूर रहेंगे। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का माला पहना कर स्वागत किया गया कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे जिसमें महेंद्र सिद्ध, बुद्धनाथ सिद्ध, संदीप सैनी, मुकेश सिद्ध , महेश, रौनक, मोहन राम जाट, इनायत खान, छगनलाल सारण, सुनील सैनी, जयप्रकाश प्रजापत, अनिल सैनी, सुशील सैनी, हरीश सुथार आदि उपस्थित थे।

'जन समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी पहली प्राथमिकता'

रतनगढ़ (निसं)। पूर्व विधायकअभिनेश महर्षिने गुरुवार को शहर के वार्ड नंबर 31 में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा किजन समस्याओं का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता है, जनहित में कोई भी कार्य विलंबित नहीं होने दिया जाएगा।महर्षि ने कहा कि भाजपा संगठन एवं कार्यकर्ता लगातार वार्डों में जाकर जनता की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान कर रहे है। सड़क निर्माण कार्य के शुभारम्भ के दौरान वार्डवासियों ने करीब 15 घरों में सीवरेज कनेक्शन नहीं होने और पानी की समस्या की जानकारी दी। शिकायत मिलते ही महर्षि ने तत्परता दिखाते हुए एलएनटी और पीएचईडी अधिकारियों को मौके पर बुलाकर त्वरित कार्रवाई कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।

अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्यवाही शुरू किए जाने पर वार्डवासियों ने संतोष प्रकट किया और पूर्व विधायक महर्षि व भाजपा नेताओं का पुष्पहार एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया।भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि वार्ड 31 में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य राजकुमार चौधरी के घर से वीरा मंदिर तक, वहां से प्राचीन श्री श्याम मंदिर के रास्ते ज्यान मोहम्मद छींपा के नोहरे तक लगभग 23.24 लाख रुपयेकी लागत से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब पूरी होने जा रही है।सैनी ने बताया कि पूर्व विधायक महर्षि के नेतृत्व में भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रतिदिन विभिन्न वार्डों में जाकर समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आमजन को बडी राहत मिल रही है। इस पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंगलाल गुर्जर, जिला प्रवक्ताओम महर्षि, निरंजन रुथला, प्रवीण शर्मा, हिम्मत सिंह मालासी, अरुण रामगढिया, किशन सैनी, भींवराज प्रजापत, नरेंद्र गुडेसर, राकेश प्रजापत, राकेश रूथला, नरेंद्र पंवार नदीम चेजारा, किशन स्वामी, भंवरलाल स्वामी, प्रभूदत्त इंदौरिया, कन्हैयालाल चौमाल, रामकिशन गोरिसरिया, सुशील इंदौरिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शपथ एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीकर, (निसं)। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता पखवाड़े के द्वितीय दिवस पर चिकित्सा विभाग के समन्वय से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शपथ कार्यक्रम एवं महिला हिंसा मुक्त वातावरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सभागार सीकर में किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आमजन को भारतीय संविधान के मूल्यों, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, समानता, गरिमा एवं न्याय की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजेन्द्र चौधरी द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई तथा वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस सहायता 112 एवं अन्य सरकारी सहायता सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को हिंसा मुक्त, सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी का सामूहिक दायित्व है, जिसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सजग, संवेदनशील एवं सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

उप निदेशक महिला अधिकारिता ने अवगत कराया कि 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक चलने वाले इस पखवाड़े के अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों के सहयोग से निरंतर जागरूकता गतिविधियां, शपथ कार्यक्रम, संवाद एवं परामर्श शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध एक मजबूत एवं सकारात्मक सामाजिक वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अशोक महरिया, डॉ. अंकुर सागवान, भोलाराम (डब्ल्यूएचओ फील्ड मॉनिटर), स्वास्थ्यकर्मी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस व मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया

सीकर, (निसं)। चिकित्सा विभाग की ओर से गुरूवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा माह की 27 तारीख होने के कारण प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस मौके पर चिकित्सालयों में चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और जीवनरक्षक टीके लगाए गए।

■ गर्भवती महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर लगाए जीवनरक्षक टीके

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया कि हर माह की 9, 18 व 27 तारीख को विभाग की ओर से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं का समाधान किया जाता है। वहीं प्रत्येक गुरूवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती व बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं।

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विशाल सिंह ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं की हिमोग्लोबिन, एचआईवी, सिफलिस, ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन व प्रसव से संबंधित जटिलताओं की जांच की गई। साथ ही गर्भवती महिला के शरीर में कैल्शियम व खून की कमी नहीं आए, इसके लिए आईएफए, कैल्शियम और अन्य आवश्यक दवाइयां दी। गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का दुगुना ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच तथा टीके लगवाने चाहिए। दिन में कम से कम तीन बार भोजन करना चाहिए और प्रसव सरकारी अस्पताल में ही करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरूवार को बच्चों को पीलिया, टीबी, हैपेटाइटिस बी, गलघोंटू, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, मेनिनजाइटिस खसरा और रूबले, रोटा, दस्त आदि रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए और उनको प्रसवपूर्व देखभाल के बारे में जानकारी दी गई।

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विशाल सिंह ने गुरूवार को जिले के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा गर्भवती व बच्चों को दी गई सेवाओं व सुविधाओं को परखा। उन्होंने जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर्ष, मंडावरा, खोरी डूंगर, चौखा का बास, बिड़ोली व बानूडा पीएचसी का निरीक्षण कर स्टॉफ की उपस्थिति, साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, जांचों की स्थिति, उपकरणों का रखरखाव, टीकाकरण, प्रसव व एएनसी की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण, प्रसव व एएनसी के लक्ष्य के अनुसार उपलब्धी अर्जित करने के निर्देश दिए।

संविधान दिवस पर जागरूकता अभियान

रतनगढ़, (निसं)। तालुका विधिक सेवा समिति,रतनगढ़ के तत्वावधान में न्यायालय परिसर में संविधान दिवस समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा तालुका अध्यक्षश्री सुरेंद्र कौशिकने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है, जो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है।

कार्यक्रम के दौरान समिति के सदस्य गौतम नाथोलिया, अधिवक्ता प्रमोद इंदौरिया, पीएलवा जितेंद्र नाथोलिया,लक्ष्मी देवी सहित टीम द्वारा शहर में व्यापक विधिक जागरूकता अभियानचलाया गया। टीम ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल, न्यायालय परिसर तथा नगर पालिका क्षेत्र में विशेष रूप से भ्रमण कर आमजन को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी दी।

बिना दहेज शादी कर सामाजिक सुधार का संदेश दिया, बारातियों को हेलमेट दिए

चूरू (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित अग्रसेन नगर निवासी व अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष रिछपाल सिंह चारण व नीरज कविया ने अपने पुत्र जयवर्धन सिंह सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ का विवाह मंगलवार 25 नवम्बर को गुमानपुरा लोसल हाल निवासी सीकर के भरत सिंह कविया की पुत्री सुनीता कंवर के साथ सम्पन्न किया।

इस विवाह समारोह में चारण परिवार ने एक सकारात्मक पहल करते हुये बिना दहेज शादी कर समाज सुधार का संदेश दिया। चारण ने बताया कि शादी में सभी रस्मों में लेन-देन से दूरी बनाई गई और दहेज जैसी कुप्रथा को बंद किया गया।

वहीं वधू पक्ष की ओर से चूरू में चारण छात्रावास के लिए 5 लाख रुपए का योगदान दिया गया और सभी बारातियों को हेलमेट भेंट कर सड़क

चारण परिवार ने एक सकारात्मक पहल करते हुये बिना दहेज शादी कर समाज सुधार का संदेश दिया।

सुरक्षा का संदेश दिया गया और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने का संकल्प दिलाया। विवाह में शामिल गणमान्य जनों ने वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान कर इस पहल को समाज में नई चेतना लाने वाला बताया।

सार-समाचार

लोक अदालत के बारे में जानकारी दी

सादुलपुर, (निसं)। राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रविन्द्र कुमार के निर्देशन में गुरूवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू डॉ. शरद कुमार व्यास द्वारा रालसा जयपुर द्वारा जारी अभियान न्याय आपके द्वारा के अंतर्गत स्थानीय बार संघ राजगढ में एक कैपेसिटी बिल्डिग कार्यक्रम का आयोजन किया। दोपहर सवा दो बजे दी जानकारी के अनुसार उक्त कार्यक्रम के दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ मुनेश चंद यादव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ नीलम मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ मंयक मीणा, अध्यक्ष बार संघ राजगढ विक्रमपाल जांगिड एवं स्थानीय बार संघ राजगढ के अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सचिव डॉ शरद कुमार व्यास द्वारा उपस्थित अधिवक्तागणों को स्थाई लोक अदालत क्या है? स्थाई लोक अदालत की स्थापन कौन करता है, स्थाई लोक अदालत की अधिकारिता क्या है, स्थाई लोक अदालत में मामला कैसे दायर किया जाता है, स्थाई लोक अदालत की प्रक्रिया क्या है, स्थाई लोक अदालत के अवॉर्ड की कानूनी वैधता क्या होती है, स्थाई लोक अदालत में कौनसे मामले नहीं आते, स्थाई लोक अदालत का लाभ क्या है, स्थाई लोक अदालत से संबधित महत्वपूर्ण निर्णय, किन-किन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर पीएलए का अधिकार है। पीएलए में प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी, पीएलए आमजन के लिए क्यों उपयोगी? कौन कर सकता है, शिकायत? इत्यादि विषयों पर पावर पोइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिग कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता प्रीतम कुमार शर्मा द्वारा किया गया।

प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता

सीकर (निसं)। शिक्षा नगरी सीकर का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते हुए सीएलसी के सीबीएसई विद्यालय सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल ने ग्वालियर में आयोजित उद्यिमता-2025 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉर्पोविटा क्विज में प्रथम स्थान तथा ट्रस्ट द यूनिकॉर्न प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सीआईएस के कॉमर्स संकाय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से सिंधिया स्कूल ग्वालियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर सहित देशभर के 20 प्रतिष्ठित स्कूलों को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की और सीकर सहित पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। विस्तृत जानकारी देते हुए सीआईएस प्रिंसिपल सुषमा भदौरिया ने बताया कि प्रतियोगिता 25 व 26 नवम्बर को ग्वालियर में आयोजित हुई जिसमें स्कूल के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वैश्विक नवाचारों एवं उद्यिमता कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सीआईएस निदेशक समर चौधरी ने विजेता विद्यार्थियों, उनके मार्गदर्शक शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि सीएलसी हमेशा से शिक्षा के साथ-साथ वास्तविक जीवन कौशल और नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए समर्पित रहा है। विद्यार्थियों की यह उपलब्धि साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और संकल्प से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। इन उपलब्धियों ने सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धित को एक बार फिर सिद्ध किया है।

इज्तिमा के समापन पर दो दर्जन से ज्यादा जोडों का सामूहिक निकाह होगा

बीदासर (निसं)। कस्बे के नेक नगर स्थित आदर्श कॉलोनी में चल रहें तीन दिवसीय विशाल दीनी तब्लीगी इज्तिमा के दूसरे दिन गुरुवार को भी जिलेभर से हजारों लोगों का इज्तिमागाह में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इज्तिमा के दूसरे दिन उलेमाओं ने दीनी मजलिस में कहां कि दुनिया में जिंदगी पैगंबर मोहम्मद साहब के बताएं हुए तरिकों पर गुजारनी चाहिए। गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। दिखावा और फिजूलखर्ची से बचकर शादियों को सरल बनाएं। सभी को पांच वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढनी चाहिए। आखिरत की तैयारी के लिए दुनिया में शरियत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। दूसरी और इज्तिमागाह में बने विशाल पांडाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक साथ नमाज अदा की जा रही है। वहीं इज्तिमा में विभिन्न कमेटियों के सैंकड़ों वॉलिंटियर्स जगह-जगह पार्किंग, यातायात, पानी, बिजली, खाना, साफ-सफाई आदि व्यवस्थाओं में जुटे हुए है। वहीं इज्तिमा के दूसरे दिन राजस्थान तब्लीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना चिरागुदीन भी इज्तिमागाह पहुंचे। जिनका उलेमाओं ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वहीं इज्तिमा के समापन पर शुक्रवार को 2 दर्जन से ज्यादा जोडों का सामुहिक निकाह होगा। इसके साथ ही सुबह 10 बजें विशाल दुआं का आयोजन होगा। इज्तिमा की हजरत मौलाना चिरागुदीन दुआ करवाऐंगे। जिसमें जिलेभर के हजारों लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की सफलता को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग तन, मन और धन से सहयोग कर रहे है। इज्तिमा के दूसरे दिन चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने शिरकत की।

बाबल परिवार ने सामाजिक समरसता की अनोखी मिसाल पेश की

झुंझुनूं (निसं)। भाजपा नेता राजेश बाबल और जिला परिषद सदस्य पूजा बाबल के भतीजे, रिटायर्ड एक्सएन कृष्ण कुमार बाबल व संगीता रानी के पुत्र पुनीत बाबल की शादी सामाजिक समरसता और सद्भाव का अनूठा उदाहरण बनी। इस विवाह समारोह में बाबल परिवार ने परंपराओं से परे जाकर ऐसे कदम उठाए, जिनकी क्षेत्रभर में चर्चाएँ हो रही हैं। शादी के दौरान वाल्मिकी समाज की महिलाओं सहित घरेलू कार्यों में सहयोग देने वाले स्टाफ और ऑफिस स्टाफ के परिजनों को विशेष सम्मान दिया गया। उन्हें विवाह मंडप में अग्रिम पंक्तियों में बैठाया गया, ताकि उन्हें भी समारोह का वही सम्मान और आनंद मिल सके, जो अन्य मेहमानों को मिलता है। इतना ही नहीं, बाबल परिवार ने सारे औपचारिक काम-पोशाक को एक तरफ रखकर स्वयं आगे बढ़कर इन अतिथियों को भोजन परोसा। इस सादगी और सम्मान से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया। समारोह में मौजूद लोगों ने कहा कि बाबल परिवार ने समानता और सामाजिक भाईचारे का जो संदेश दिया है, वह आज के समय में अत्यंत प्रेरणादायक है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की इस पहल की क्षेत्र के लोगों ने खुलकर सराहना की। पुनीत बाबल की शादी सिर्फ़ एक खुशियों का अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द का सुंदर उदाहरण बन गई।

निःशुल्क आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन

सादुलपुर, (निसं)। चानणमल अध्यक्ष महाराज अग्रसेन भवन सादलपुर बजरंग लाल सत्यनारायण डोकवे वाले परिवार के आर्थिक सौजन्य से प्रत्येक माह की 27 तारीख को आयोजित होने वाले निःशुल्क आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन गुरूवार को नवनिर्मित श्याम मंदिर राजगढ में किया गया। दोपहर सवा एक बजे मिली जानकारी के अनुसार निःशुल्क आयुर्वेदिक कैंप का शुभारंभ चाणनमल डोकवेवाला अध्यक्ष अग्रसेन भवन सादुलपुर सानिध्य में हुआ। जिसमें समस्त अतिथियों ने डोकवे वाले परिवार द्वारा कैंप लगाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने रोगों से संबंधित रोगियों को प्रत्येक माह की 27 तारीख को नवनिर्मित श्याम मंदिर राजगढ में को पहुंचने का आवहान किया। गणेश दाधीच जानकारी देते हुए बताया डॉक्टर महावीर सिंह ने कैंप में 71 रोगियों की निःशुल्क जांच कर दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर अनिरुद्ध पाटोदिया एडवोकेट, राजकुमार सांखोलिया, प्रमोद चंगोई वाला, जतिन, कमलेश, संत कुमार सरावगी, मंगतू राम दाधीच व वीरेंद्र राठौड आदि उपस्थित थे।

'पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना अनिवार्य'

सीकर, (निसं)। जिला कोषाधिकारी विक्रम सिंह भूकर ने बताया कि निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान-जयपुर के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के समस्त सिविल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने पेंशनर्स एवं उनके परिजनों से अनुरोध किया है कि यथासंभव आज या कल तक ही जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा दें, ताकि पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे। पेंशनर्स निम्न किसी भी सुविधाजनक तरीके से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं। राजकीय कार्मिक (राजपत्रित/अराजपत्रित) अपनी के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर आधार बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) से प्रमाणीकरण करवाएं। पेंशन पोर्टल पर स्वयं निर्धारित प्रपत्र अपलोड करें। निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित कोषागार/उपकोषागार कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करें।

भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ दांव पर होता है, लेकिन कोच बल्ला लेकर खेल में नहीं उतर सकता। खिलाड़ियों को प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। - आर. अश्विन

भारतीय गेंदबाज, दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी: दीप्ति शर्मा

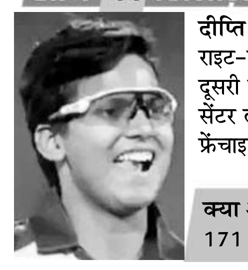

दीप्ति शर्मा टाटा डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में यूपी वरियर्ज को राइट-टू-मैच के जरिए 3.2 करोड़ रुपये में बिकने वाली दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं। जियोहॉटस्टार के 'मैच सेंटर लाइव ऑक्शन स्पेशल' पर बात करते हुए, दीप्ति ने फ्रेंचाइजी में वापसी को लेकर अपनी खुशी शेयर की, अपनी बैटिंग में आए बदलाव का क्रेडिट डब्ल्यूपीएल को दिया, और अपनी सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली नई टीममेट के तौर पर फ़ोबे लिचफ़ील्ड को चुना। अलग-अलग टीमों के नए प्लेयर्स को यूपी वरियर्ज में शामिल होते देखकर मुझे बहुत पॉज़िटिव महसूस हो रहा है।

क्या आप जानते हैं ?... टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट डेल स्टेन के नाम है। उन्होंने 93 मैच की 171 पारी में 439 विकेट चटकाए हैं।

चतुर्थ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता

रोहन का अर्द्धशतक बेकार, जसवंत व अनामिक ने कृष्णा को 1 रन से जीत दिलाई

जयपुर, 27 नवम्बर। मैत्री क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित आज हुकम सिंह क्रिकेट ग्राउण्ड हाथोज में चतुर्थ डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम स्मृति टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्तर्गत्त आज खेले गये पूल-सी के मुकाबले में कृष्णा क्रिकेट एकेडमी ने जसवंत चौहान 37 रन, 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट के ऑलराउण्ड प्रदर्शन तथा अनामिक 21 रन पर 3 विकेट की शानदार गेंदबाजी की बदौलत शास्त्री क्रिकेट एकेडमी को रोहन सिंह 56 रन के अद्धर्शतक के बावजूद रोमांचक मैच में 1 रन से हराकर महत्वपूर्ण 2 अंक अर्जित किये। टॉस जीतकर कृष्णा क्रिकेट एकेडमी पहले बल्लेबाजी करते हुए जसवंत चौहान 37 रन, दर्शन जैन 20 रन, राहुल शर्मा 20 रन, दिनेश यादव 20 रन, जितेन्द्र यादव 14 रन, अनामिक 13 रन व सौरव बद्री 12 रन नाबाद की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोर 143 रन बनाये। गेंदबाजी में शास्त्री क्रिकेट एकेडमी की ओर से एस.एस. शर्मा, तनवीर खान, सुहान पठान, हर्ष सैनी व अल्तमश शेख प्रत्येक 1-1 विकेट लेकर सफल गेंदबाज रहे। जवाबी पारी में शास्त्री क्रिकेट एकेडमी ने अपने 4 विकेट 5 ओवर में मात्र 31 रन पर गवा दिये। 5 विकेट पर रोहन सिंह 56 रन (40 गेंद, 5 चौके, 3 छक्के), मुकीम 31 रन ने मिलकर पांचवे विकेट पर 85 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाकर मैच शास्त्री क्रिकेट एकेडमी के पक्ष में कर दिया। लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज हर्षित शर्मा 18 तथा कप्तान हर्ष सैनी 12 रन ने अपनी टीम को चौके, छक्के मारकर जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन कृष्णा क्रिकेट एकेडमी के गेंदबाजों ने अनामिक 21 रन पर 3 विकेट, राहुल शर्मा 25 रन पर 2 विकेट तथा जसवंत चौहान 24 रन पर 1 विकेट ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुये शास्त्री क्रिकेट एकेडमी की टीम को 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन तक सीमित कर दिया और बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में मात्र 1 रन से विजय हासिल कर ली। इस मैच का मैन ऑफ दी मैच जसवंत चौहान कृष्णा क्रिकेट एकेडमी रहे।

असम जनवरी में संतोष ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल राउंड की मेजबानी करेगा

नई दिल्ली, 27 नवंबर। संतोष ट्रॉफी 2025-26 के लिए 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल राउंड जनवरी 2026 में असम में होगा। ग्रुप स्टेज 15 से 26 दिसंबर तक नौ जगहों पर होंगे। ग्रुप स्टेज में 35 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें नौ ग्रुप होंगे (आठ ग्रुप में चार टीमें और एक ग्रुप में तीन टीमें)। ग्रुप विनर मेजबान असम, पिछले सीज़न के चैंपियन पश्चिम बंगाल और रनर-अप केरल के साथ 12 टीमों के फाइनल राउंड में शामिल होंगे, जो ढकुआखाना और धेमाजी में होस्ट किया जाएगा। असम ने पिछली बार 2010-11 सीजन में संतोष ट्रॉफी फाइनल राउंड की मेजबानी की थी, जब पश्चिम बंगाल ने मणिपुर को हराकर गुवाहाटी में ट्रॉफी जीती थी।

अफगानिस्तान अंडर-19 टीम ने भारत को 65 रनों से हराया

बेंगलुरु, 27 नवंबर। कप्तान महबूब खान (50) और अजीज़ुल्लाह मिआखिल (60) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान अंडर-19 टीम ने गुरुवार को त्रिकोणीय श्रृंखला के छठे एकदिवसीय मुकाबले में भारत ए अंडर-19 टीम को 65 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान की टीम चार मैचों में तीन जीत के साथ 12 अंकों लेकर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी है।

बीसीसीआई अंडर-23 वीमेन टी-20 में राजस्थान जीती

जयपुर, 27 नवम्बर। बीसीसीआई अंडर 23 वीमेन टी 20 ट्रॉफी (राजस्थान -जम्मू कश्मीर मैच) राजस्थान जीती। नागपुर में आज खेले गए राजस्थान - जम्मू कश्मीर मैच में राजस्थान ने जम्मू कश्मीर को 7 विकेट से हराया। जम्मू कश्मीर पारी 114 / 4, टीम के लिए बावनदीप 43, मान्या 44 रन। राजस्थान की गेंदबाज सिद्दी शर्मा, शानू, याना 1-1 विकेट। राजस्थान पारी 117/3, टीम के लिए चंद्रज्योत्सना नाबाद 50, पार्वती 24, डिंपल कँवर 22 व अंजलि जाट नाबाद 12 रन।जम्मू कश्मीर की गेंदबाज मान्या 12 / 2 विकेट।

अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी मैच हेतु राजस्थान टीम घोषित

जयपुर, 27 नवंबर। बीसीसीआई की अंडर 19 कूचबिहारट्रॉफी (डेज) के लिए विधर्भ के विरुद आगामी मैच के लिए राजस्थान जूनियर चयन कमेटी ने राजस्थान टीम का चयन किया। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी (डेज) के लिए घोषित राजस्थान टीम :- कुशाग्र ओझा (कप्तान), मनय कटारिया (उपकप्तान), आदित्य सैनी, नावेदखान, जतिन सैनी, हनी प्रताप सिंह, अभिषेक मूंड, केतन देवासी, देवांश जैसवाल, रजत बघेल, रक्षित लुनावत, प्रखर शर्मा, शुभांकर त्यागी, गौरव, विनोद कुमावत।

ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत को दिये जाने का किया स्वागत

यह ग्लोबल स्पोर्टिंग प्रतियोगिता के सौ साल पूरे होने का जश्न : बेन ह्यूस्टन

ग्लासगो (स्कॉटलैंड), 27 नवंबर। ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत को दिये जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह ग्लोबल स्पोर्टिंग प्रतियोगिता के सौ साल पूरे होने का जश्न है।

कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष बेन ह्यूस्टन ने भारत को बधाई देते हुए कहा, अमदाबाद, हम आ रहे हैं। भारत को हमारी बधाई, एक मजबूत और सोची-समझी बोली के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक नए अध्याय की शुरुआत करती है, गेम्स की सौवीं सालगिरह मनाने के लिए एक मेजबानी देती है, और ऑस्ट्रेलिया के एथलीटों को ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स से केवल दो साल पहले मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। ह्यूस्टन ने कहा, राष्ट्रमंडल खेल अभियान के लिए यह पल कितना अहम है, इसे कम

आंकना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विक्टोरिया 2026 के कैंसिल होने से सिस्टम को झटका लगा है, जिसमें कॉमनवेल्थ के देशों ने न केवल अगले साल ग्लासगो को होस्ट करने के लिए, बल्कि 2030 के लिए एक जोशीला होस्ट और भविष्य के गेम्स का स्वागत करने के लिए तैयार और काबिल शहरों की एक लाइन के लिए भी पूरी तरह से तैयार रिस्पॉन्स देखा है।

उन्होंने कहा, हम राष्ट्रमंडल खेलों इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड और बिड प्रोसेस में शामिल सभी लोगों की उनकी कोशिशों के लिए तारीफ करते हैं और ऐसे भविष्य की उम्मीद करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एथलीटों के लिए प्रेरणा देने वाले और असरदार मौके देगा। अहमदाबाद के 2030 का मेजबान शहर की पुष्टि होने के साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्पोर्ट्स की एक शुरुआती सूची भी जारी की।

एथलेटिक्स और पैरा-एथलेटिक्स, बाउल्स और पैरा-बाउल्स, बॉक्सिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, स्विमिंग और पैरा-स्विमिंग, टेबल टेनिस और पैरा-टेबल टेनिस, और वेटलिफ्टिंग और पैरा-पावरलिफ्टिंग सभी को शामिल किया गया है। अब 2030 के बाकी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को तय करने के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। गेम्स में कुल 15 से 17 खेल होने की उम्मीद है, और आखिरी कार्यक्रम की 2026 में पुष्टि होगी।

दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में भारत की हार के बाद ऋषभ पंत ने माफी मांगी

नई दिल्ली, 27 नवंबर। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में नेशनल टीम के खराब प्रदर्शन के बाद गुरुवार को इंस्टाग्राम पर माफ़ी मांगी, और माना कि भारत ने "पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला" और उन्होंने मजबूत वापसी का वादा किया।

पंत ने लिखा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। माफ करना, हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है - एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर भी।"

यह मैसेज भारत की दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद आया है, इस नतीजे की फैंस और पुराने खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की है। भारत को दो बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें टेस्ट इतिहास में रनों से उसकी सबसे बड़ी हार भी शामिल है। उन्होंने कहा, भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, और एक टीम और अकेले के तौर पर और मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।

अभी तक की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) विनर, दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में दूसरे और आखिरी टेस्ट में एशियन जायंट्स को 408 रनों से हराया, जहां पंत, शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारत के स्टैंड-इन कैप्टन थे, जो गर्दन में ऐंठन के कारण बाहर हो गए थे। गुवाहाटी में यह हार टेस्ट क्रिकेट में रनों के मामले में भारत की सबसे बड़ी हार थी। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान असर डालने में नाकाम रहे। पंत ने चार इनिंग्स में 12.25 के खराब औसत से सिर्फ 49 रन बनाए।

सोफी डिवाइन दो करोड़ की राशि के साथ जीटी की टीम में हुई शामिल

नई दिल्ली, 27 नवंबर। सोफ़ी डिवाइन डब्ल्यूपीएल 2026 में गुजरात जायंट्स की टीम से खेलेंगी। उन्हें 2 करोड़ की बड़ी राशि के साथ टीम में शामिल किया गया है। गुजरात जायंट्स ने डब्ल्यूपीएल नीलामी में उन पर 50 लाख रुपये पर पहली बोली लगाई। इसके बाद आरसीबी ने इंट्रेस्ट दिखाया और बोली बढ़ती चली गई। 1.1 करोड़ रूपये पर दिल्ली कैपिटल्स ने एंट्री मारी थी, लेकिन गुजरात किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लगातार बोलियां लगती रहीं और अंत में गुजरात को सफलता मिली। वहीं एलिसा हीली के लिए किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है। उन्हें 2023 में यूपी वॉरियर्स ने 70 लाख रुपये में खरीदा था। उल्लेखनीय है कि नवी मुंबई में 9 जनवरी को डब्ल्यूपीएल 2026 की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट नवी मुंबई और वड़ोदरा के दो वेन्यू पर खेला जाएगा। फ़ाइनल 5 फरवरी को वड़ोदरा में होगा।

भारतीय हॉकी टीम ने न्यूज़ीलैंड को 3-2 से हराया

इपोह, (मलेशिया), 27 नवंबर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड 3-2 से हराया। भारत के लिए अमित रोहिदास ने (चौथे), संजय ने (32वें), और सेल्वम कार्थी ने (54वें) मिनट में गोल दागे। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से जॉर्ज बेकर ने (42वें और 48वें) मिनट में गोल किए। आज यहां सुल्तान अजलान शाह कप स्टेडियम में खेले गये मैच के पहले कुछ शुरुआती मिनटों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर बढ़त बनाई। भारत ने एक अच्छे मूव से अपना पहला मौका बनाया, जिससे उसे पेनल्टी कॉर्नर मिला और अमित रोहिदास ने (चौथे) मिनट में गोलकर स्कोरिंग शुरू की। पहला क्वार्टर 1-0 की बढ़त के साथ खत्म हुआ।

भारत ने मलेशिया को 7 गोल के रोमांचक मुकाबले में हराया

इपोह, 27 नवंबर। भारतीय हॉकी टीम ने बुधवार को इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में मेजबान मलेशिया को 4-3 के रोमांचक मुकाबले में हराया। सेल्वम कार्थी (7'), सुखजीत सिंह (21'), अमित रोहिदास (39') और संजय (53') ने दुनिया की नंबर 7 टीम भारत के लिए गोल किए, जबकि फैजल सारी (13'), फितरी सारी (36'), और मरहान जलील (45') ने 12वीं रैंक वाली मलेशिया के लिए गोल किए। मलेशिया पर जीत के साथ भारत सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 की स्टैंडिंग में तीन गेम में छह पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।

तन्वी शर्मा ने पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 नोजोमी ओकुहारा को चौंकाया

लखनऊ, 27 नवंबर। 16 साल की तन्वी शर्मा ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के तीसरे दिन करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने पूर्व वर्ल्ड नंबर 1, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट नोजोमी ओकुहारा को तीन गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर तहलका मचा दिया।

वर्ल्ड जूनियर्स सिल्वर मेडलिस्ट ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई, एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सिर्फ़ एक घंटे से भी कम समय में 13-21, 21-16, 21-19 से यादगार जीत हासिल की - यह उनके छोटे करियर का सबसे बड़ा नतीजा था, जिससे उन्होंने क्वार्टर फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उलटफेर यहीं नहीं रुके। इशारानी बरुआ ने एक और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, उन्होंने यूक्रेन की आठवीं सीड पोलिना बुहरोवा को 21-15, 21-8 से हराया। टॉप सीड उन्नित हुड्डा ने तस्नीम मीर को 21-15, 21-10 से हराकर आराम से जीत हासिल की, जबकि रक्षिता श्री ने देविका सिहाग को 16-21, 21-19, 21-17 से हराया।

मेन्स सिंगल्स में, तीसरे दिन और भी सरप्राइज़ आए, जब मनराज सिंह ने तीसरे सीड एचएस प्रणय को 21-15, 21-18 से हराया। मिथुन मंजूनाथ ने छठे सीड थारुन मन्नेपल्ली को 21-16, 17-21, 21-7 से हराया, जबकि पूर्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सनीथ दयानंद को 21-6, 21-16 से आसानी से हराया।

टॉप सीड विमेंस डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए ज़ेनिथ एबिगेल/लिखिता श्रीवास्तव को 21-17, 21-12 से हराया। जॉली ने हरिहरन अम्साकारुनन के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में दूसरे सीड रोहन कपूर/रुथविका गड्डे को 24-22, 21-15 से हराया। मेन्स डबल्स में, हरिहरन और एमआर अर्जुन ने मलेशिया के लाउ यी शेंग/लिम त्ज़े जियान को 21-12, 21-18 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की की।

सिंडारोव दूसरे रैपिड गेम मेंकाले मोहरों से वेई यी को हराकर चैम्पियन बने

पणजी, 27 नवंबर। उज़्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंडारोव बुधवार को यहां टाईब्रेक में चीन के ग्रैंडमास्टर वेई यी को हराकर सबसे कम उम्र के फिडे वर्ल्ड कप 2025 चैंपियन बन गए। 19 साल के सिंडारोव दूसरे रैपिड गेम में काले मोहरों से वेई को हराकर वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले उज़्बेक शतरंज खिलाड़ी बन गए और 120,000 डॉलर की इनामी राशि के साथ-साथ नया विश्वनाथन आनंद कप भी अपने नाम किया। फिडे वर्ल्ड कप 2025 एक सिंगल-एलिमिनेशन नॉक-आउट टूर्नामेंट की तरह खेला गया था और इसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ियों ने एक कॉम्पिटिशन में जीत और कैंडिडेट्स 2026 में तीन जगह पाने की कोशिश की थी।

के. श्रीकांत की धमाकेदार जीत, प्रियांशु राजावत व उन्नति हुडा भी अंतिम आठ में

लखनऊ, 27 नवंबर। स्टार भारतीय शटलर के.श्रीकांत ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में गुरुवार को उम्दा खेल दिखाते हुए एकतरफा जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान सुरक्षित कर लिया। दिन के सबसे बड़े उलटफेर में पुरुष एकल में तीसरी वरीय भारत के एचएस प्रणय और महिला एकल में जापान की नोजोमी ओकुहारा आश्चर्यजनक हार के साथ बाहर हो गए। महिला एकल में शीर्ष वरीय उन्नित हुड्डा, पुरुष एकल में पिछले साल के सेमीफाइनलिस्ट प्रियांशु राजावत और महिला युगल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी.भी अंतिम आठ में पहुंच गए। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में गुरुवार कई उलटफेर भरे मुकाबलों का गवाह बना।

आईसीसी ने पर्थ की पिच को बहुत अच्छा कहा

दुबई, 27 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पर्थ में खेले गये पहले एशेज टेस्ट मैच जो कि दो दिन में सामप्त हो गया था कि पिच को बहुत अच्छी श्रेणी का करार दिया है। मैच रेफरी रंजन मदुगले की ओर से पिच को लेकर दी गई आधिकारिक रिपोर्ट में इसे बहुत अच्छा करार दिया गया है। आईसीसी के चार-टियर पिच रेटिंग सिस्टम के अनुसार, बहुत अच्छा का मतलब है ऐसी पिच जिसमें अच्छी पकड़, लिमिटेड सीम मूवमेंट, और मैच की शुरुआत में लगातार बाउंस हो, जिससे बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बराबरी का मुकाबला हो सके।" यह टेस्ट मैच 847 गेंदों के साथ यह ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे छोटा पूरा हुआ टेस्ट था और 1888 के बाद से फेंकी गई गेंदों के हिसाब से सबसे छोटा एशेज टेस्ट था। पहली तीन पारियों में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 58 रन देकर सात विकेट लिए, हालांकि पहले दिन चाय से पहले इंग्लैंड का स्कोर 160 रन पर पांच विकेट था। मेहमान टीम का अटैक फिर भी लगातार चलता रहा और आखिर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 123 रन पर नौ विकेट हो गया, जिसमें बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लिए। पहले दिन 305 रन पर 19 विकेट गिरे, जबकि दूसरे दिन, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 205 रन के लक्ष्य को केवल एक सत्र में हासिल कर लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जेम्स ऑलसॉप ने कहा कि तीसरे और चौथे दिन के टिकट रखने वाले फैंस के लिए यह निराशाजनक था, लेकिन उन दो दिनों में कुछ जबरदस्त क्रिकेट के साथ एशेज में जान आ गई। मैच रेफरी की बहुत अच्छी रेटिंग हमारे इस विश्वास को सही साबित करती है कि पर्थ स्टेडियम ने ऐसी पिच बनाई जिसमें बल्ले और गेंद के बीच सही बैलेंस था। दोनों तरफ से कुछ शानदार तेज गेंदबाजों का दबदबा और मुकाबले का जबरदस्त माहौल का मतलब था कि मैच केवल दो दिन चला। उन्होंने कहा, "तीसरे और चौथे दिन के टिकट रखने वाले फैंस के लिए यह निराशाजनक था, लेकिन हमने कुछ शानदार पल देखे जिन्होंने बहुत सारे दर्शकों को अपनी ओर खींचा और इस गर्मी में और भी बच्चों को बल्ला और गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेंगे।"

हम एक-दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और मजबूत होंगे : गिल

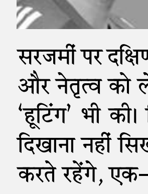

नई दिल्ली, 27 नवंबर। गर्दन की चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेलने वाले कप्तान शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका से श्रृंखला 0-2 से हारने के बाद एकजुटता और पक्का इरादा दर्शाते हुए कहा कि इस हार के बावजूद टीम और मजबूत होगी। टेस्ट मैच की श्रृंखला शर्मनाक रही। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में पहले टेस्ट में 30 रन से और गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को 408 रन से हराकर क्लीन स्वीप किया। यह भारतीय सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका की 25 साल में पहली जीत थी। इस हार से टीम के प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर आलोचना शुरू हो गई और प्रशंसकों ने कोच गौतम गंभीर की 'हूटिंग' भी की। गिल ने बुधवार को 'एक्स' पर लिखा, "शांत समुद्र आपको रास्ता दिखाना नहीं सिखाता, बल्कि तूफान ही मजबूत बनाता है। हम एक-दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मजबूत होंगे।

बुरी तरह हारने के बाद प्रशंसकों ने की गंभीर की 'हूटिंग'

नई दिल्ली, 27 नवंबर। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनने के बाद पहली बार गौतम गंभीर की बुधवार को यहां बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कुछ प्रशंसकों के समूह ने 'हूटिंग' की जो दक्षिण अफ्रीका से दूसरे टेस्ट में मिली 408 रन की हार से काफी नाराज थे। गंभीर ने 2024 में यह पद संभाला था। हार से नाराज गुस्से में प्रशंसकों ने एक स्टैंड में 'गंभीर हाय हाय, वापस जाओ' के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर स्टेडियम के अंदर ये नारे जोर जोर से गूंजने लगे। कोच ने कुछ देर के लिए गैलरी की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुरंत ही खिलाड़ियों का ध्यान भी इस ओर गया। अंतिम एकादश के कई सदस्यों का ध्यान भी उनके नारों से भीड़ पर गया और वे इस हंगामे को घूर रहे थे। तभी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। इसके तुरंत बाद सिराज और सहायक कोच सितांशु कोटक गैलरी के पास गए और उन्होंने इन खेल प्रेमियों से शांति की अपील की। समर्थकों का गुस्सा साफ दिख रहा था।

रामबाग और लेपर्ड टीमें जीती

जयपुर, 27 नवंबर। जयपुर सीजन 2025 के अंतर्गत खेले जा रहे कोटा कप 6 गोल टूर्नामेंट में आज पीपीसी ग्राउंड पर रामबाग और सुहाना ऑल स्टार्स टीमों केब ीच मैच खेला गया। जिसमें रामबाग ने सुहाना टीम को 4 गोल के मुकाबले 9 गोलों से हराया रामबाग टीम की ओर से शमशीर अली ने अपने शानदार खेल दिखाते हुए 5 गोल किये। डेनियल ने 3 गोल और सिद्धांत शर्मा ने 1 गोल किया। जबकि सुहाना ऑल स्टार्स टीम की ओर से हूर्ट अली ने 4 गोल किये पर अफनी टीम की हार नहीं टाल पाये। दूसरे मैच में चूंडा पोलो टीम को लेपर्ड ने 8 के मुकाबले 8.5 गोल से हराया। चूंडा टीम की ओर से शुभम गुप्ता ने 1 गोल, विशाल राठौड़ ने 2 गोल और फ्रेडरिक ने बेहतरीन खेल खेलते हुए 5 गोल किये। आधे गोल का एडवॉन्टेज लेकर खेल रही लेपर्ड टीम की ओर से मयूरध्वज ने 1 गोल, मृत्युंजय सिंह ने 2 गोल और भवानी सिंह कालवी ने 4 गोल किये।

भव्या के सातवें स्विमिंग गोल्ड ने जैन यूनिवर्सिटी की टॉप पर जगह पक्की कर दी

जयपुर, 27 नवंबर। जैन यूनिवर्सिटी की स्विमर भव्या सचदेवा ने गुरुवार को यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में इंडिविजुअल इवेंट्स में दो गोल्ड मेडल जीते और महिलाओं की 4100 मेडले रिले में एक गोल्ड मेडल जीतकर अपने कुल पदकों की संख्या सात कर ली।

भव्या, जिन्होंने कॉम्पिटिशन के पहले दो दिनों में एक इंडिविजुअल और एक रिले गोल्ड जीता था, ने गुरुवार को महिलाओं की 800मी फ्रीस्टाइल कैटेगरी में 9:37.41 की टाइमिंग के साथ अपना गोल्ड मेडल मार्च शुरू किया। इस साल की शुरुआत में एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, कुछ मिनट बाद पूल में लौटीं और 200मी फ्रीस्टाइल इवेंट में 2:13.55 के टाइम के साथ जीत हासिल की।

जैन यूनिवर्सिटी के तैराकों ने उम्मीद के मुताबिक पूल इवेंट्स में दबदबा बनाया, 11 में से आठ गोल्ड मेडल जीतकर अपने कुल गोल्ड मेडल टैली को 20 तक पहुंचा दिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बीच मेडल टैली में दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर थी, क्योंकि लवली ने आर्चरी में

तीन और शूटिंग में एक गोल्ड मेडल जीतकर अपने गोल्ड मेडल टैली को 13 तक पहुंचा दिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अब तक 14 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें फेंसिंग में तीनों टीम गोल्ड और गुरुवार को शूटिंग में एक गोल्ड मेडल शामिल है।

तीरंदाज अंशिका कुमारी और देवांग गुप्ता ने रिकर्व पुरुष और महिला फाइनल जीते, और फिर शाम को एलपीयू को टीम गोल्ड दिलाने के लिए लौटे। जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला रिकर्व फाइनल में, अंशिका ने पंजाब यूनिवर्सिटी

की सृष्टि जायसवाल को 6-2 से हराया, जबकि गुप्ता ने पुरुष रिकर्व फाइनल में शिवाजी यूनिवर्सिटी के साहिल शेलार को 6-4 से हराया। टीम इवेंट में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 6-0 से हराया, जबकि पुरुषों ने शिवाजी यूनिवर्सिटी को 6-2 से हराया।

हालांकि, अंशिका और गुप्ता को रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल में झटका लगा, वे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की कार्तिका विचपुरिया और दीपांशु नंदा से टाईब्रेकर में हार गए। उसी कॉम्प्लेक्स में कुछ मीटर दूर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के राजकंवर सिंह संधू ने 25मी रैपिड फायर पिस्टल में 29 के फाइनल स्कोर के साथ गोल्ड जीता, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के देवांश वशिष्ठ को सिर्फ एक पॉइंट से हराया।

साक्षी पाडेकर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण जीतने के बाद

भावुक साक्षी ने कहा, मुझे पता था कि परफेक्ट शॉट के लिए शांत रहना बेहद जरूरी है। मैंने बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और इस दिन के लिए बहुत मेहनत की। आज वह सब रंग लाया।

पुरुषों के 10मी एयर राइफल इवेंट में, यश वर्धन ने फाइनल में 252.7 के स्कोर के साथ मणिपाल यूनिवर्सिटी, राजस्थान के लिए गेम्स का पहला गोल्ड मेडल जीता। यश और केएलईएफ यूनिवर्सिटी के सिल्वर मेडलिस्ट मद्दीनेनी उमा महेश पूरे फाइनल में बराबरी पर थे, लेकिन फाइनल सीरीज के पहले शॉट में 10.8 के स्कोर ने उन्हें मेडल दिलाया, क्योंकि उनके सबसे करीबी विरोधी सिर्फ 9.9 ही बना पाए।

बीकानेर में दूसरी तरफ, लोगेश्वरन एस ने वेटलिफ्टिंग इवेंट्स के तीसरे दिन शानदार परफॉर्मेंस देते हुए अपना पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोल्ड मेडल जीता। तिरुवल्लूर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, तमिलनाडु में जन्मे इस लिफ्टर ने पुरुषों की 79 किग्रा कैटेगरी में कुल 305किग्रा उठाकर दबदबा बनाया - 135 किग्रा स्नैच में और 170 किग्रा क्लीन एंड जर्क में - यह उनकी तीसरी केआईयूजी अपीयरेंस में एक बड़ी कामयाबी थी।

दोपहर के सेशन में पुरुषों की 88 किग्रा कैटेगरी में कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के परीक्षित सोनी कुल 278 किग्रा(127किग्रा स्नैच; 151 किग्रा क्लीन एंड जर्क) उठाकर टॉप पर रहे। उन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी के एम तरुण को हराया, जिन्होंने 276 किग्रा (126 किग्रा स्नैच; 150 किग्रा क्लीन एंड जर्क) के साथ टॉप किया, जबकि गुरु काशी यूनिवर्सिटी के विवेक ने 273 किग्रा (121 किग्रा स्नैच; 152 किग्रा क्लीन एंड जर्क) उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की घोषित नीति है- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में पर्यटन के प्रीसमिट सम्मेलन को संबोधित किया

जयपुर, 27 नवम्बर। गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विकास हो रहा है। इस वर्ष अगस्त माह तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक और 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं।**

प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है। भव्य किले, महल, हवेलियां, थार का मरुस्थल, वन्यजीव अभयारण्य, आस्था धाम और झीलों की उपलब्धता राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निराला प्रदेश बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस वर्ष अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात् करते हुए, राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 योजना के अंतर्गत, खाटूश्याम जी, करणी माता मंदिर, मालासेरी डूंगरी समेत, अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया है।

प्री-समिट में उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन अपर सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, हिन्दुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा सहित, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्यमी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद थे।

'स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों की जवाब देही तय की जाए'

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया तथा ओटीटी संस्थाओं द्वारा अपनाये गये मौजूदा स्व-नियमन ढ ांचे पर असंतोष व्यक्त किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री की निगरानी के लिए एक ''तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त'' नियामक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ गुरूवार को पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में ऑनलाइन शो ''इंडियाज गॉट लैटेंट'' से संबंधित कथित अश्लील सामग्री को लेकर दर्ज प्राथमिकी को एक साथ करने की मांग की गयी है। । इससे पहले न्यायालय ने ऑनलाइन अश्लीलता पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मामले के दायरे को बढ़ ाया था। मुख्य न्यायाधीश ने स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी भी नियामक ढ ांचे की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, ''तो मैं अपना चैनल बनाता हूं, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं... किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए!'' उन्होंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ''विकृति'' को सही ठहराने के लिए नहीं बढ़ ाया जा सकता।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हार्डकोर सदस्य प्रदीप गुर्जर गिरफ्तार

एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स ने नाटकीय तरीके से गुरुग्राम की पॉश सोसायटी में उसे पकड़ा

जयपुर, 27 नवम्बर। एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स राजस्थान (एजीटीएफ) की टीम ने कार्रवाई करते हुए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक सक्रिय सदस्य और हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रदीप रावतों की ढाणी, वार्ड नंबर 15, कोटपूतली, का रहने वाला है। उसे गुड़गांव की एक पॉश सोसायटी से गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्य रूप से हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाकर उनसे जबरन रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात है। एजीटीएफ की यह कार्रवाई राज्य में संगठित अपराध और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे तीन दर्जन से अधिक संगीन अपराधों

- **पुलिस के अनुसार, हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्यतः हाईवे पर स्थित होटल संचालकों से जबरन रंगदारी वसूलने में लिप्त है।**

के मुकदमे दर्ज हैं। सात आपराधिक मुकदमों में फरार चलने के कारण एसपी कोटपुतली द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में, एक विशेष टीम को इस हार्डकोर बदमाश को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राम सिंह द्वारा किया गया। टीम ने मुखबिरों को एक्टिव किया। इसके बाद हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार को उसके गुरुग्राम में होने की पुख्ता जानकारी मिली।

यह एक चुनौतीपूर्ण मिशन था, जहाँ टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेकी की। आरोपी गुड़गांव के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र की एक विशाल और लग्ज़री सोसायटी एम आर पाम हिल के एक फ्लैट में छिपा हुआ था।

टीम ने सोसायटी के नाकों पर सदस्य तैनात किए और गार्ड बनकर हेड कांस्टेबल सुधीर ने अंदर पल-पल की जानकारी हासिल की। सटीक स्थिति का पता चलते ही टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और गैंग्स्टर प्रदीप रावत को घेर कर दबोच लिया। टीम आरोपी को कोटपूतली लेकर आई है और उसे थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अन्य मामलों के खुलासे की पूरी संभावना है।

'अगर इमरान ज़िंदा हैं तो मिलने क्यों नही दिया जा रहा'

इमरान की पार्टी के लोगों ने इमरान की हत्या की आशंका जताई

रावलपिंडी, 27 नवंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवित होने को लेकर सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा गया है। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में उनके परिवार और परिजनों को कोई खबर नहीं दी गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और जापानी मीडिया में इमरान खान की जेल में मौत होने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने साढ़े पांच बजे नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुला ली है। इससे बड़ी अनहोनी की आशंका जन्म ले रही है। इन्हीं आशंकाओं के बीच खैबरपख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी बृहस्पतिवार को जब इमरान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया।

मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से जेल में मिलने से मना कर दिया गया। इसलिए वे जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले कई दिनों से इमरान खान की मौत हो जाने की अफवाहें पाकिस्तान से लेकर

- **असल में अफगानिस्तान मीडिया ने बुधवार को दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी की अडियाला जेल में हत्या कर दी गई है, उसके बाद से ही भारी अफरातफरी का माहौल है।**

विदेशी मीडिया तक में हाहाकार मचा रही हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की खैबरपख्तूनख्वा में सरकार है। सोहेल अफरीदी इमरान खान की पार्टी के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। मगर उन्हें भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने मिलने से रोक दिया है। इमरान खान का परिवार और पीटीआई के कार्यकर्ता, शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ असिम मुनीर पर इमरान खान की जेल में ही हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हजारों इमरान समर्थक अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे यह प्रदर्शन अन्य शहरों में भी फैलता जा रहा है।

दरअसल अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी की आदियाला जेल में हत्या कर दी गई है। इससे पाकिस्तान में अफरातफरी के हालात बन गये हैं। इमरान खान के समर्थकों की मांग है कि अगर इमरान खान सुरक्षित और जीवित हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की मौत की रिपोर्ट को बकवास बताया है, लेकिन मुश्किल समय में इमरान खान को छोड़कर भागने की वजह से समर्थकों को उनकी बातों पर यकीन नहीं है।

स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन पर भाजपा समर्थकों द्वारा एक असामान्य गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, जो आमतौर पर राज्यस्तरीय मंत्रियों को राजधानी में नहीं मिलता।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर कई पूर्व-निर्धारित बैठकें हुईं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि पार्टी बिहार के बदलते राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी गंभीर है। गृह मंत्रालय पर तो भाजपा का नियंत्रण है ही, और अब वह स्पीकर पद पर काबिज होने की तैयारी में है, जिससे पार्टी के पास अब कानून-व्यवस्था और विधायी प्रक्रिया, दोनों का नियंत्रण होगा। यह दोहरा कब्जा भाजपा को बिहार में सत्ता का केन्द्र बना देता है, जिसके चलते नीतीश कुमार के पास काम करने की सीमित गुंजाइश ही बचती है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये घटनाक्रम भाजपा प्रेरित शासन के एक नए युग का संकेत हैं, जहां नीतीश मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब भाजपा के हाथों में है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में स्पेशल इन्टैंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया है। पीठ ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकेंगे, और मामले की शीघ्र सुनवाई का निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईआर लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर मौलिक चिंताएं उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर सामान्य मतदाताओं पर असंवैधानिक दबाव डालता है, जिनमें से कई निरक्षर हैं।

उन्होंने कहा, "फॉर्म भरना मतदाता की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोग निरक्षर हैं और उन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता। अगर वे फार्म नहीं भर सकते, तो उन्हें (मतदाता सूची से) हटा दिया जाएगा, उन्होंने अदालत से संविधानिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने की अपील की।"

उन्होंने कहा कि एक बार किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाने के बाद, उसकी वैधता की मान्यता स्वत: ही बन जाती है, जब तक राज्य इसका विरोध नहीं करता। "किसी भी बहिष्करण की प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए।"

सिब्बल ने यह भी कहा कि जब आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, यह धारक के पक्ष में एक अनुमान है। उन्होंने कहा, "तो मेरे पक्ष में भी एक अनुमान है। मेरे पास आधार है। वह मेरा निवास है। आप इसे हटाना चाहते हैं... तो इसे एक प्रक्रिया से हटाइए और इसे इस कोर्ट में साबित होने दीजिए।" हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने मृत मतदाताओं को सूची से हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह बताया कि सूची पंचायतों और सरकारी वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। उन्होंने कहा, "हम शून्य में निर्णय नहीं करते। सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी।

हम प्रदूषण पर तुरंत समाधान की उम्मीद नहीं करें- सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (एमसी मेहता मामला) से संबंधित मामले को अगले सोमवार को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है लेकिनद्ध न्यायालय ने आगाह किया कि न्यायपालिका से इस स्तर के संकट का तुरंत समाधान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरूवार को इस मामले की तत्काल सूचीबद्धता के उल्लेख की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक ''स्वास्थ्य आपातकाल'' है। पीठ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को तदर्थ न्यायिक निर्देशों के बजाय, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जानकारी पर निर्भर रहना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की ''खतरनाक'' स्थिति को उजागर करने वाली न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''हम समस्या जानते हैं। हमें सभी

- **सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तदर्थ न्यायिक निर्देशों की बजाय वैज्ञानिक व विशेषज्ञ जानकारी पर निर्भर रहना चाहिये।**

कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है। कोई एक अकेला कारण नहीं है, ऐसा सोचना गलती होगी।"

न्यायपालिका की सीमाओं का उल्लेख करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "कोई अदालत क्या जादुई छड़ी चला सकती है? मुझे बताएं, हम क्या निर्देश दें, ताकि तुरंत स्वच्छ हवा मिल जाए?" पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समझना आवश्यक है कि सरकार ने कौन सी समितियां बनाई हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या कर रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों में कौन से समाधान व्यावहारिक हैं।

मुंबई में सीट बंटवारे पर ठाकरे बंधुओं में मतभेद हुआ

मुंबई, 27 नवंबर। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच 75 सीटों को लेकर एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गतिरोध दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मध्य मुंबई स्थित उनके आवास शिवतीर्थ पर पूर्वाह्न में मुलाकात की।

उपभोक्ता आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। ऐसे में इसमें केसर मिलाने का दावा भ्रामक है। परिवाद में बताया गया कि विज्ञापन में दाने-दाने में केसर का दम दिखाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इससे एक ओर निर्माता कंपनी करोड़ों रुपए का व्यापार कर रही है और दूसरी ओर आमजन हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए घातक गुटखे का सेवन कर कैंसर जैसी बीमारी को न्यौता दे रहे हैं। परिवाद में गुहार की गई है कि विमल गुटखा के उत्पादन और विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाई जाए।

मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग ने तीनों अभिनेताओं और अभिनेत्री सहित निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

दिल्ली विस्फोट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकि उनका इस्तेमाल हमलों में किया जा सके।

एजेंसी के मुताबिक, वानी के खिलाफ सबूतों से पता चलता है कि उसने 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट में मदद के लिए आतंकवादी नेटवर्क को टेक्निकल सपोर्ट देना जारी रखा। ये गतिविधियां बड़े हमलों की साजिश का हिस्सा थीं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। एनआईए टीम वानी से दूसरे संभावित साथियों, ड्रोन सप्लाई नेटवर्क और टेक्निकल मॉड्यूल के बारे में पूछताछ करेगी।

एसआईआर भरते हुए बंगलादेशी गिरफ्तार

कोलकाता, 27 नवंबर। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बॉग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत गणना पत्र भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया

- **बंगलादेशी नदीम 15 साल पहले भारत आया था और आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था।**

कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था। वह तब पकड़ा गया, जब उसने स्थानीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से नौ साल पहले मर चुके मोहसिन खान का गणना पत्र हासिल किया और उसे भरने की कोशिश कर रहा था। माथुर डांगी गाँव के वार्ड नंबर 20 के मोहसिन खान के परिवार के सदस्यों ने विवरण देखने के बाद इस धोखाधड़ी को भांप लिया और उसे पकड़कर डानकुनी पुलिस के हवाले कर दिया।

इण्डो-अमेरिकन व्यापारिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन परिस्थितियों में समझौता होगा या नहीं, और यदि होगा तो किस रूप में, यह काफी हद तक दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा और समझौते की तैयारी पर निर्भर करेगा। सवाल यह है कि क्या कोई पक्ष नरमी दिखाने के लिए तैयार है?

कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि थोड़ी गुंजाइश मौजूद है। भारत कृषि व डेयरी क्षेत्र को व्यापक रूप से खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सेब, बादाम, अखरोट, कुछ प्रोसैस्ड फूड और गैर-जीएम अमेरिकी उत्पादों को सीमित मात्रा में अनुमति देने के लिए तैयार दिख रहा है। यह संकेत है कि भारत पूरी तरह बाजार खोले बिना, सीमित और नियंत्रित पहुंच देने पर विचार कर सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों (स्टील, ऑटो कॉम्पोनैंट्स) पर पहले ही भारी शुल्क लगा रखा है, जिससे यह दबाव बढ़ सकता है, खासकर उन सैक्टर्स की तरफ से, जो भारतीय सप्लाई चेन पर निर्भर हैं, कि व्यापक समझौते के बजाय सीमित छोटा समझौता स्वीकार कर लिया जाए।

फिर भी नज़दीकी समय में किसी बड़े नरम रुख की संभावना कम ही दिखती है। भारत के लिए कृषि और

- **दूसरी ओर अमेरिका भी भारतीय मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने की मांग पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं।**
- **भारत अगर कुछ नर्म पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा सेब, बादाम आदि कुछ ''कृषि उत्पादों'' को बेचने की सीमित छूट दे सकता है।**
- **लगभग यह ही स्थिति भारत के औद्योगिक उत्पाद, जैसे स्टील, ऑटोपाट्र्स, टैक्सटाइल्स के बारे में है।**
- **अतः तुरंत, आनन-फानन में ''ट्रेड डील'' हो जाए, मुमकिन नहीं लगता। कुछ छोटी-मोटी मिनी ''ट्रेड डील'' जरूर हो सकती है।**

डेयरी सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा का आधार हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में सुरक्षा कम करने पर तीखी घरेलू प्रतिक्रिया हो सकती है। वहीं अमेरिका की कृषि लॉबी और खेती के सामान के निर्यातक भी भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर पहुंच की मांग छोड़ने वाले नहीं हैं।

ऐसे में सबसे अधिक संभावना यही है कि एक सीमित या "मिनी-डील" बन सकती है, जिसमें औद्योगिक व गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क संबंधी रियायतें शामिल होंगी, और कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों को नियंत्रित एवं सीमित शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। यह राजनीतिक और व्यापारिक रूप से दोनों देशों के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

संक्षेप में, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावटें खेती, डेयरी और रैगुलेटरी ऑटोनोमी में हैं। दोनों पक्षों के लिए समझौता नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह आर्थिक फायदों और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन बनाने पर निर्भर करेगा।

क्या बुलेट ट्रेन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईसीटीएस-2 सिग्नलिंग को लागू करने का इरादा भी किया है, लेकिन इस पर विचार-विमर्श जारी है। जून में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (एनएचआरसीएल) - जो एमएएचएसआर की कार्यान्वयन एजेंसी है - ने सिग्नलिंग और टेलीम्यूनिकेशंस कार्यों के लिए डीआरए-इन्फ्राकॉम सीमन्स संयुक्त उपक्रम को 4140 करोड़ रुपये का अनुबंध सौंपा। सीमन्स ने भारतीय रेलवे के प्रबंधकों को यह आश्वासन दिया है कि "ड्यूल-यूज़" सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे, ताकि अगर भारत के सार्वजनिक परिवहन ने बाद में लीकी केबल सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया तो वह इसके लिए तैयार हो गया।

दिल्ली- मेरठ रैपिड रेल और दिल्ली मेट्रो के लिए अपनाई गई रणनीतियों के अनुरूप, भारतीय रेलवे 320 किमी/घंटा की गति वाली ट्रेनसेट्स के लिए "वेंडर न्यूट्रल" सिग्नलिंग सिस्टम प्राप्त करने की योजना बना रहा है, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी की भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, इन बिड्स को बाद में जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि, भारतीय रेलवे की पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी या उपकरण खरीदने की मंशा जापान के साथ विवाद पैदा कर सकती है, जो परियोजना के वित्तपोषक हैं। दिसंबर 2015 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत, एक सेट वस्त्रों को जापान से खरीदना अनिवार्य होगा। शेष सामग्री के लिए जापान की स्वीकृति आवश्यक होगी। एमएएचएसआर पर कार्य कर रहे ठेकेदार पहले ही जापान की हठधर्मी के कारण पश्चिमी देशों से आयात किए गए सामान को मंजूरी देने में समस्या का सामना कर रहे हैं। एक कंपनी ने इस साल जर्मनी से आयातित कुछ घटकों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लगभग 50 करोड़ रुपये का नुकसान बताया है। इस कंपनी ने अब यूरोपीय निर्माताओं से और अधिक आयात करने की योजना रोक दी है।

असम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है, यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है, जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उससे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उनकी शादी कानूनी रूप से रद्द नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह कदम सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच गहरे मतभेदों को दर्शायेगा, जिनके बीच कांग्रेस की 2023 की बड़ी जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव है।

संभावित विकल्प के रूप में गृह मंत्री जी. परमेश्वर का नाम सामने आया है। वे सिद्धारमैया समर्थक और प्रभावशाली दलित नेता हैं। उन्होंने हाल में कहा, "मैं हमेशा से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहा हूं," जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई।

यह रणनीति बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली की अगुवाई में हुई बैठक में तय की गई। जारकीहोली सिद्धारमैया के करीबी हैं। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि पार्टी के दिल्ली नेतृत्व को यह सवाल अब निपटाना ही होगा। जारकीहोली की शिवकुमार से भी मुलाकात हुई, लेकिन बैठक का विवरण सामने नहीं आया।

खड़गे और गांधी परिवार गुरुवार या शुक्रवार को इस मसले पर अंतिम चर्चा कर सकते हैं। खड़गे ने पत्रकारों से कहा, "सोनिया, राहुल और मैं इस समस्या का समाधान कर देंगे।"

योजना यह है कि खड़गे-गांधी बैठक के बाद, सिद्धारमैया और शिवकुमार, दोनों को दिल्ली बुलाया जाएगा।

उधर डीके शिवकुमार ने अब तक टकराव की स्थिति नहीं बनाई है और राजनीतिक रूप से संतुलित बयान दिए हैं। उन्होंने तो अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पद, जिसे वे चाहते हैं, पर बने रहने का समर्थन भी सार्वजनिक रूप से किया है और अपने समर्थन में आए बयानों - जैसे रामनगर के विधायक इकबाल हुसैन का "200 प्रतिशत पक्का" वाला बयान, को भी हल्का किया है।

लेकिन उन्होंने कई बार संकेतों में तीखी बातें भी कही हैं, जिनमें वादों को निभाने की याद दिलाना शामिल है। माना जाता है कि उनका इशारा सीधे सिद्धारमैया की तरफ था।

सिद्धारमैया-शिवकुमार विवाद कांग्रेस की 2023 जीत के बाद शुरू हुआ। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया को चुना, जबकि शिवकुमार का मानना था कि जीत दिलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, इसलिए यह पद उन्हें मिलना चाहिए था।

इसके बजाय उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया, पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहने दिया गया। कांग्रेस का "एक व्यक्ति, एक पद" नियम इस मामले में ढीला किया गया। उसी समय एक 'समझौता' चर्चा में था, जिसका जिक्र शिवकुमार ने "हम पांच-छह लोगों के बीच हुआ गुप्त समझौता" कहकर किया था, जिसके अनुसार, आधे कार्यकाल के बाद सिद्धारमैया पद छोड़ देंगे।

पांच साल के कार्यकाल का मध्य बिंदु पिछले सप्ताह पार हो गया। तब से शिवकुमार खेमे के विधायक परिवर्तन की मांग जोर-शोर से उठा रहे हैं। शिवकुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे पद चाहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने का संकेत भी दिया था, जो मुख्यमंत्री पद पाने की इच्छा का प्रतीक है।

ईडी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण विवरण लीक करने के एवज में रिश्वत दी गयी थी। आरोप है कि इस जानकारी के लीक होने से मेडिकल कॉलेजों को जरूरी मापदंडों में हेरफेर करने और अवैध रूप से अनुमोदन लेने में मदद मिली। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, उनमें सात मेडिकल कॉलेज और निजी आरोपियों के ठिकाने शामिल हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600